● वर्ष-4
● अंक-92
रायपुर, मंगलवार
26 नवंबर 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6» चंद्र की उत्पत्ति कैसे हुई...

रची गई थी सुनियोजित साजिश

संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा, कई धर्मगुरु भी इसमें शामिल

लखनऊ। संभल में हिंसा भड़काने की साजिश सुनियोजित थी। हमलावरों ने पुलिस बल पर पत्थरबाजी से शुरूआत की, चंद मिनटों बाद छतों से पुलिसकर्मियों पर सीधे गोलियां चलानी शुरू कर दी गईं। पुलिस ने मोर्चा संभाला तो भीड़ ने गाड़ियों में आग लगानी शुरू कर दी। हालात काबू में करने के बाद अब पुलिस आरोपियों को तलाश रही है ताकि उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सके। साथ ही साजिश रचने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जिनमें कुछ धर्मगुरू भी शामिल हैं।

उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो मुस्लिम समुदाय की नाराजगी मस्जिद के सर्वे को लेकर थी, लेकिन जानबूझकर पुलिस को निशाना बनाया गया। कुछ मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 315 बोर की गोली लगने की पुष्टि हुई है। वहीं कुछ शवों में गोलियां शरीर के आर-पार होने का पता चला है, जिनकी गहनता से जांच कराकर पता लगाया जा रहा है कि किसी बोर के असलहे से चली गोली उन्हें लगी थी। फिलहाल संभल में हालात काबू में हैं। संभल पुलिस को दी गई चार कंपनी पीएसी और एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है और विवादित परिसर को छावनी में तब्दील किया जा चुका है। जिन इलाकों में हिंसा भड़की थी, वहां पर पुलिस लगातार छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। डीजीपी मुख्यालय हर दो घंटे में संभल पुलिस से रिपोर्ट ले रहा है, जिसे शासन और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जा रहा है। संभल हिंसा के बाद प्रदेश के संवेदनशील जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। खासकर जिन जिलों में संभल की तरह मंदिर-मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, वहां खास चौकसी बरतने के निर्देश डीजीपी मुख्यालय द्वारा दिए गए हैं। इन जिलों में सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि संभल की घटना का फायदा उठाकर माहौल खराब करने की साजिश अंजाम नहीं दी जा सके। अधिकारियों की मानें तो संभल पुलिस ने जिस तरह उपद्रवियों से मोर्चा लिया, उससे कई लोगों की जान बची है। पुलिस ने पहले उपद्रवियों पर काबू पाने के तमाम प्रयास किए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम की मदद से उनको घरों में वापस जाने की संभ्रांत नागरिकों से अपील कराई गई। इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आने पर पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी। अब पुलिस यह पता लगा रही है कि हिंसा भड़कने के बाद किन धर्मगुरुओं ने भड़काऊ बयान देकर माहौल को और बिगाड़ने का प्रयास किया था।

उपद्रवियों से नुकसान की भरपाई, जांच के आदेश

जामा मस्जिद के नजदीक से शुरू हुए बवाल ने शहर की आधी आबादी को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। जगह जगह उपद्रवियों ने आगजनी की और तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। गली मोहल्ले और प्रतिष्ठानों पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए। पुलिस और प्रशासन के पास ऐसे वीडियो और फोटो हैं। जिसमें वह बवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन उपद्रवियों ने जो सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। उसकी वसूली भी इन्हीं उपद्रवियों से की जाएगी। डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बताया कि उपद्रव के दौरान जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन कराया जा रहा है। इसके बाद जो भी धनराशि आकलन रिपोर्ट के आधार पर तय होगी उसकी वसूली की जाएगी। इसके अलावा जिन लोगों को पाबंद किया गया था। उनसे भी वसूली की जाएगी। 42 लोगों को नोटिस तामील कराए गए थे। इनमें जिनकी भी भूमिका बलवे में रही है। उन सभी से वसूली होनी है। प्रशासन अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। संभल में बवाल के दौरान हुई मौतों की न्यायिक जांच होगी। रविवार की देर रात को ही डिप्टी कलक्टर मुख्यालय दीपक कुमार चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। घटना कैसे हुई, क्या-क्या नुकसान हुआ और मौत किन कारणों से हुई है। इन जैसे सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जांच होनी है।

केंद्र सरकार ने दी पैन 2.0 और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन को मंजूरी

नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने सोमवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए। बैठक में 1435 करोड़ रुपये की लागत वाली पैन 2.0 योजना को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पैन कार्ड हमारे जीवन का हिस्सा है। यह मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। इसे अपग्रेड किया गया है। इसके तहत मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस किए जाएंगे। नए पैन कार्ड क्यूआर कोड वाले होंगे। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसके लिए अलग से कोई शुल्क नहीं लगेगा। नए पैन में डाटा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एक शिकायत निवारण तंत्र तैयार किया जाएगा।

कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले

छात्रों को मिल सकेंगे अंतरराष्ट्रीय जर्नल

वैष्णव ने कहा कि युवाओं और छात्रों के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। कैबिनेट ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन (एक राष्ट्र एक सदस्यता) योजना को मंजूरी दी है। 6,000 करोड़ रुपये की लागत वाली यह योजना में कुल 30 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पत्र-पत्रिका प्रकाशकों को शामिल किया गया है। इसमें लगभग 13,000 ई-जर्नल का सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा और छात्रों, संकायों और शोधार्थियों को मुहैया कराया जाएगा। इन संसाधनों का 6,300 से अधिक सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों और केंद्र सरकार के अनुसंधान एवं विकास संस्थान साझा करेंगे।

अटल इनोवेशन मिशन के दूसरे संस्करण को मंजूरी

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2750 करोड़ की लागत से अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को मंजूरी दी है। युवाओं को नवाचार और उद्यमिता में आगे लाने के लिए भारत में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत हुई थी। हमें पता लगा था कि अटल इनोवेशन मिशन के पहले संस्करण में स्थानीय भाषा को शामिल नहीं किया गया था। इसलिए हमने अटल इनोवेशन मिशन 2.0 को लागू किया है। इसके तहत 30 ऐसे नवाचार केंद्र खोले जाएंगे जो स्थानीय भाषा में काम करेंगे।

प्राकृतिक खेती को दिया जाएगा बढ़ावा

केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाते हुए 2,481 करोड़ रुपये के राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन पर मुहर लगाई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार किसानों के कल्याण के लिए काम कर रही है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एनएमएनएफ) का उद्देश्य एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक और बिना खाद के खेती की ओर प्रेरित करना है। यह योजना मिट्टी की सेहत सुधारने और लागत कम करने के साथ टिकाऊ खेती का वातावरण तैयार करेगी। अभी देश भर में लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती हो रही है। इस योजना के कुल परिव्यय 2,481 करोड़ रुपये में भारत सरकार का हिस्सा 1,584 करोड़ रुपये और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपये है।

इन परियोजनाओं पर भी लगी मुहर

बैठक में अरुणाचल प्रदेश में दो जल बिजली परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इस पर 3,689 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बैठक में रेलवे की तीन बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। 160 किमी लंबी मनमाड-जलगांव चौथी लाइन बनेगी। इससे हर साल आठ करोड़ लीटर डीजल की बचत होगी। वहीं दूसरी परियोजना में भुसावल से खंडवा तक तीसरी और चौथी लाइन का काम होगा। इससे पूर्वांचल और मुंबई के बीच क्षमता बढ़ेगी। इस परियोजना पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे रोजगार शुरू होगा और किसानों, छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री साव ने नव दम्पत्तियों को उपहार प्रदान कर शादी की बधाई दी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुंगेली जिले के लोरमी में आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने समारोह में 14 नव दंपत्तियों को उपहार और विवाह प्रमाण पत्र प्रदान कर शादी की बधाई और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सभी के सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा लोरमी के मंगल भवन में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में 14 जोड़ों की पारम्परिक रीति-रिवाज से शादी सम्पन्न कराई गई।

छत्तीसगढ़ में होगी एकलव्य विद्यालयों की राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता

रायपुर। नई दिल्ली स्थित जनजातीय कार्य मंत्रालय के राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों की चतुर्थ राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता 2024-25 का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के सफल संचालन हेतु क्रियान्वयन एजेंसी के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

इसके लिए भारतीय खेल प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के इम्पेनल्ड एजेंसियों से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई है। प्री-बिड का बैठक 27 नवंबर 2024 और प्रेजेंटेशन 29 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे होगा। 02 दिसंबर 2024 को दोपहर 3 बजे तक दस्तावेज़ जमा कर सकेंगे और 02 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे वित्तीय निविदा खोला जाएगा।

प्रमुख समाचार

40 बागी विधायकों में से 5 को मिली हार

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को उनके राजनीति छोड़ने के वादे की याद दिलाई, यदि 2022 में अविभाजित शिवसेना के विभाजन के दौरान उनके साथ रहने वाले बागी विधायकों में से कोई भी राज्य में विधानसभा चुनाव हार गया। पार्टी के मुखपत्र %सामना% में एक लेख में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट ने शिंदे को याद दिलाया कि 40 बागी विधायकों में से पांच विधानसभा चुनाव हार गए हैं। दैनिक ने कहा कि विधायक हैं माहिम से सदा सरवनकर, भायखला से यामिनी जाधव, सांगोला से शाहजी बापू पाटिल, मेहकर से संजय रायमुलकर और उमरगा से ज्ञानराज चौगुले। शिंदे की सेना की ओर से एकनाथ शिदने को मुख्यमंत्री बने रहने की मांग बढ़ने के बाद पार्टी की ओर से यह प्रतिक्रिया आई है। शिव सेना (यूबीटी) के प्रवक्ता नरेश म्हस्के ने शिंदे के समर्थन में बिहार में व्यवस्था का हवाला दिया। म्हास्के ने कहा कि हमें लगता है कि शिंदे को मुख्यमंत्री होना चाहिए, ठीक उसी तरह जैसे बिहार में हुआ था, जहां बीजेपी ने संख्या को नहीं देखा, लेकिन फिर भी जेडीयू नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाया। महायुति (महाराष्ट्र में) के वरिष्ठ नेता अंतत: निर्णय लेंगे।

शिवसेना (यूबीटी) विधायक दल के नेता चुने गए आदित्य

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में एकतरफ जहां महायुति फिर से सरकार बनाने में जुट गई है, वहीं विपक्ष में मौजूद महा विकास अघाड़ी की घटक दल शिवसेना (उद्धव बालासाहब ठाकरे) ने अपने जीते विधायकों के साथ बैठक कर विधायक दल का नेता, विधानसभा में पार्टी के नेता और मुख्य सचेतक का चुनाव किया है। शिवसेना (यूबीटी) की आज हुई बैठक पर पार्टी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि, बैठक में भास्कर जाधव को विधानसभा में पार्टी का नेता और सुनील प्रभु को मुख्य सचेतक चुना गया। आदित्य ठाकरे को शिवसेना (यूबीटी) विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में मुख्य मुकाबला महायुति और महा विकास अघाड़ी गठबंधनों के बीच था। जिसमें महायुति ने बाजी मारते हुए 288 विधानसभा सीटों में से 230 सीटों पर जीत हासिल की है। इसमें भाजपा ने अकेले 132 सीट, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार गुट की एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है। महायुति गठबंधन के तीनों घटक दल भाजपा, शिवसेना और एनसीपी क्रमशः राज्य की शीर्ष तीन पार्टियां हैं।

डूसू चुनावः 10 साल बाद बना एनएसयूई का अध्यक्ष

नई दिल्ली। आखिरकार, डूसू 2024 चुनाव परिणाम आज, 25 नवंबर को घोषित कर दिए गए हैं। यह एनएसयूआई और एबीवीपी के बीच एक करीबी मुकाबला रहा। डूसू 2024 चुनाव में दोनों पार्टियों ने दो-दो पद हासिल किए हैं। ष्ठस् 2024 चुनाव में एनएसयूआई ने अध्यक्ष और संयुक्त सचिव पद पर कब्जा किया है, जबकि एबीवीपी ने उपाध्यक्ष और सचिव पद पर कब्जा किया है। चुनाव परिणाम अदालत के आदेश के कारण देरी से घोषित किए गए, जिसके तहत विश्वविद्यालय परिसर से पोस्टर, होर्डिंग्स और भित्तिचित्रों सहित विरूपण सामग्री को हटाने की आवश्यकता थी। कॉलेज स्तर के चुनावों में, एबीवीपी ने पांच कॉलेजों में क्लीन स्वीप हासिल किया है, जबकि एनएसयूआई ने दो कॉलेजों में सभी पद हासिल किए हैं। अध्यक्ष पद के लिए एनएसयूआई के उम्मीदवार ने अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की, जबकि एबीवीपी के भानु प्रताप ने उपाध्यक्ष पद हासिल किया है। सचिव पद के लिए एबीवीपी के मित्रविंदा कर्णवाल ने और संयुक्त सचिव पद के लिए एनएसयूआई के लोकेश चौधरी ने स्थान हासिल किया है।

हार कर भी जीत गए प्रशांत किशोर, बढ़ाई तेजस्वी की टेंशन

नई दिल्ली। चुनावी रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर ने अतीत में कई राजनीतिक दलों के लिए शानदार जीत दिलाई है। हालांकि, अब वह अपनी पार्टी बना चुके हैं। प्रशांत किशोर की जन सुराज ने बिहार में चार सीटों पर हुए उपचुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे थे। लेकिन उपचुनाव में उनकी पार्टी जीत हासिल करने में असफल रही। अक्सर भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के रूप में जाने जाने वाले किशोर ने इस साल 2 अक्टूबर को अपनी पार्टी लॉन्च की और एक अलग पहचान बनाने की दिशा में कदम उठाया। लेकिन दो महिने पुरानी पार्टी को जितना वोट मिला, उससे अन्य पार्टियों की चिंता जरूर बढ़ गई होगी। जन सुराज ने चार उम्मीदवारों को मैदान में उतारा- तरारी में किरण सिंह, बेलागंज में मोहम्मद अमजद, इमामगंज में जीतेंद्र पासवान और रामगढ़ में सुशील कुमार सिंह कुशवाहा। रविवार को जब नतीजे घोषित हुए तो सिंह अमजद और पासवान तीसरे स्थान पर रहे, जबकि कुशवाहा चौथे स्थान पर रहे। हालांकि हार गए, प्रदर्शन इतना अच्छा है कि एक महीने पुरानी राजनीतिक पार्टी के लिए किसी का ध्यान नहीं गया।

इस्कॉन के चिन्मय प्रभु पर कार्रवाई, देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार

ढाका. बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन करने पर इस्कॉन के चिन्मय कृष्ण दास प्रभु पर कार्रवाई की गई है। उनको देशद्रोह और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में बांग्लादेश पुलिस ने ढाका एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया। इसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोग ढाका की सड़कों पर उतर पड़े और जाम लगा दिया।चिन्मय प्रभु चटगांव जाने के लिए हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पहुंचे थे। जहां से गिरफ्तार कर पुलिस उनको जासूसी शाखा के कार्यालय ले आई। इस्कॉन के सदस्यों ने कहा कि पुलिस ने कोई गिरफ्तारी वारंट नहीं दिखाया। चिन्मय प्रभु ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के विरोध में कई रैलियां की हैं। इन रैलियों में उन्होंने लगातार अंतरिम सरकार के खिलाफ हमला बोला है। चिन्मय प्रभु बांग्लादेश में सनातन जागरण मंच के प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहे हैं। 30 अक्तूबर को बांग्लादश में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने के आरोप में देशद्रोह अधिनियम के तहत चिन्मय कृष्ण दास प्रभु समेत 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला

संविधान से क्यों नहीं हटेंगे समाजवादी व पंथनिरपेक्ष शब्द

शिवेंद्र तिवारी

देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल करने को चुनौती दी गई थी। इन याचिकाओं को प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने सोमवार को खारिज कर दिया। इससे पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंथनिरपेक्षता पर अहम टिप्पणी की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पंथनिरपेक्षता को हमेशा संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना जाता रहा है।

पहले जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना क्या है?

भारतीय संविधान की %प्रस्तावना% एक संक्षिप्त परिचयात्मक कथन है। प्रस्तावना किसी दस्तावेज के दर्शन और उद्देश्यों को बताती है। इसे 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था। दरअसल, 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने संवैधानिक ढांचे का वर्णन करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 1947 (22 जनवरी) में इसे अपनाया गया। इसने भारत के संविधान को आकार दिया और इसका संशोधित रूप भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होता है।

प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया?

केशवानंद भारती मामले के फैसले के बाद यह स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। संविधान के एक भाग के रूप में, प्रस्तावना को संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

अभी तक प्रस्तावना में केवल एक बार

42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के जरिए संशोधन किया गया है। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के जरिए प्रस्तावना में जोड़े गए। संप्रभु और लोकतांत्रिक के बीच समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिए गए। राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया।

तो कोर्ट में प्रस्तावना को लेकर क्या याचिका दाखिल की गई?

शीर्ष अदालत में भाजपा नेता डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी, सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय और बलराम सिंह ने इसे लेकर याचिकाएं दाखिल की थीं। याचिकाओं में 1976 में 42वें संशोधन के जरिये संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए दो शब्दों पंथनिरपेक्ष और सामाजवाद को हटाने की मांग की गई। याचिकाओं में कहा गया कि ये दोनों शब्द 1949 में तैयार किए गए संविधान के मूल प्रस्तावना में नहीं हैं। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई की और 22 नवंबर को आदेश सुरक्षित रखा था।

याचिकर्ताओं की मांग क्या थी?

याचिकाकर्ताओं में एक अश्विनी उपाध्याय ने शीर्ष अदालत में अपनी याचिका के जरिए कई बिंदु उठाए। याचिकाकर्ता न कहा कि वह न तो %समाजवादी, %पंथनिरपेक्ष% और अखंडता% शब्दों के खिलाफ हैं और न ही संविधान में उनके समावेश के खिलाफ है, बल्कि वह इन शब्दों को 1976 में प्रस्तावना में शामिल किए जाने के खिलाफ हैं।

याचिकाकर्ता उपाध्याय ने कहा कि भारत, एक देश के रूप में, संविधान के मौलिक अधिकारों और अन्य प्रावधानों के होने के कारण स्वाभाविक रूप से पंथनिरपेक्ष है। प्रस्तावना में केवल एक शब्द जोड़ने से देश में कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ा। तर्क दिया गया कि अगर पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा जा सकता है तो संप्रभु, लोकतांत्रिक, न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और अखंडता जैसे शब्दों को हटाया जा सकता है। साम्यवाद जैसे शब्दों को भी प्रस्तावना में जोड़ा जा सकता है।

समाजवादी शब्द को लेकर याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह देश के लिए एक व्यक्तिपरक विषय है। आज लोग समाजवाद को पसंद कर सकते हैं लेकिन कल उन्हें साम्यवाद पसंद आ सकता है जो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। यहां तक कि डॉ. बीआर अंबेडकर ने भी संविधान सभा में यह तर्क दिया था।

आगे तर्क दिया गया है कि प्रस्तावना 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाने का एक कथन है और इसलिए कथन नहीं बदला जा सकता। हालांकि, आपातकाल के काले दिनों के दौरान सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान सभा की ओर से, जो 1976 में अस्तित्व में नहीं थी, और यहां तक कि कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना, संविधान को अपनाने की तारीख यानी 26 नवंबर 1949 को बदले बिना प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष, अखंडता को शामिल किया। याचिकाकर्ता ने कहा है कि संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वह प्रस्तावना के तथ्यों को नहीं बदल सकती।

उपमुख्यमंत्री साव ने सफाई कर्मचारियों के पखारे पांव

साव ने जन्मदिवस के अवसर पर मां महामाया से लिया आशीर्वाद

■ पीएम आवास योजना के हितग्राहियों को सौंपी मकान की चाबियां

बिलासपुर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने अपने जन्म दिवस पर रतनपुर में सफाई कर्मचारियों का पद प्रक्षालन कर उनका सम्मान किया और ऐतिहासिक नगरी के गौरव को लौटाने का वादा किया। महामाया देवी के दर्शन कर उन्होंने राज्य की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जनदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी । कार्यक्रम में लगभग 2 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की गई, जिसमें 30 लाख रुपए के छह ई-रिक्शा भी शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा रतनपुर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व है। पिछले 10 महीनों में 6 करोड़ रुपए की योजनाओं को पूरा किया गया है। हम इस नगरी के गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए ईमानदारी से कार्यरत हैं। जन्म दिवस पर उप मुख्यमंत्री को कार्यकर्ताओ ने लड्डुओं से तौला और मिठाई वितरित किया । कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में सामाजिक संगठनों और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंटकर शुभकामनाएं दीं।

समाज के अंतिम व्यक्ति तक सीधे पहुंच रही भाजपा सरकार की योजनाएं : नंदनी नेताम

गरियाबंद। गरियाबंद मैनपुर विकासखंड के एक-एक गाँव जाकर ज़मीनी स्तर पर भाजपा की सक्रिय कार्यकर्ता श्रीमती नंदनी नेताम दौरा कर रही है और लोगों की समस्याओं को लेकर राज्य सरकार के पास जाकर उनका निराकरण भी करवा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र में भाजपा सरकार आने के पश्चात पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व में अपनी एक अनोखी और विशिष्ट पहचान बनाई है। आज विश्व एक उभरती हुई

महाशक्ति के रूप में भारत को देख रहा है। भारत रक्षा के क्षेत्र में अपनी अतुलनीय मजबूती के कारण हर चुनौती से उबरने के लिए सदैव तैयार है। यह तभी संभव है जब आप कार्यकर्ताओं की बदौलत एक मजबूत और दृढ़ निश्चयी सरकार चुनकर लाते है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में 2023 में पूर्ण बहुमत के साथ दोबारा आई है तब से सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को सर्वोपरि रखा है। राज्य सरकार अंत्योदय की परिकल्पना के साथ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंच रहा है और पहुंचाते भी रहेगी। 70 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में सीधे 1000 रुपये प्रतिमाह दे रही है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पिछले 9 माह से सुधरती हुई नजर आ रही है।

पीएम आवास योजना से मिलने लगी तन-मन को शांति

■ शान्ति बाई ने दीया - श्रीफल से किया गृह प्रवेश

कोरिया। संघर्षों से भरा जीवन जी रही कोरिया जिले के ग्राम गिरजापुर की श्रीमती शांति बाई के लिए अपना पक्का मकान कभी एक सपना था। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी और उन्हें वह खुशी प्रदान की, जो उन्होंने वर्षों से चाही थी।

स्वर्गीय धर्मपाल की पत्नी श्रीमती शांति बाई, जिन्होंने वैधव्य के साथ जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, अपनी पूरी ताकत से परिवार का पालन- पोषण करती रही हैं। उनके दो बच्चे और आठ सदस्यीय परिवार की आजीविका मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। बरसों से कच्चे मकान में रह रही शांति बाई पक्के घर की चाह में थीं, लेकिन सीमित संसाधनों ने उनके इस सपने को साकार होने नहीं दिया।

वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत श्रीमती शांति बाई को मकान निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त हुआ। इस योजना ने उनकी उम्मीदों को नया पंख दिया। योजना के तहत मिली आर्थिक सहायता का सही उपयोग करते हुए उन्होंने तेजी से अपने मकान का निर्माण कार्य पूरा किया।

गृह प्रवेश का दिन श्रीमती शांति बाई के लिए एक भावुक और ऐतिहासिक क्षण था। जनपद पंचायत बैकुंठपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अलेक्जेंडर पन्ना ने ग्राम पंचायत सरपंच और ग्रामीणों की उपस्थिति में शांति बाई को उनके नए पक्के मकान की चाबी सौंपी। गृह प्रवेश के दौरान उनके चेहरे पर संतोष और खुशी के भाव छलक रहे थे। उन्होंने थाली में दीया, कुमकुम, पीले चावल और श्रीफल से गृह प्रवेश किया। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और श्री विष्णु देव साय सरकार को प्रधानमंत्री आवास मिलने पर धन्यवाद दिया।

शांति बाई ने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना ने मेरे जैसे जरूरतमंदों को जीने की नई राह दी है। अब मेरे पास अपना पक्का मकान है, जो मुझे सामाजिक सुरक्षा और सम्मान का अहसास कराता है।

अब मैं और मेरा परिवार शांति और सुकून के साथ जीवन बिता सकेंगे।ष् आज श्रीमती शांति बाई का परिवार अपने पक्के मकान में सुकून और गरिमा के साथ रह रहा है और यह उनकी मेहनत, संघर्ष और सरकार की सहायता का साकार रूप है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा

पुराने घर को फर्जी जियो टैग कर दिखा रहे नया, हितग्राहियों से ले रहे पैसे

सक्ती। सक्ती में पीएम आवास योजना में जमकर फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। ये आरोप गांव के लोगों और हितग्राहियों ने लगाया है। हितग्राहियों ने बताया कि रोजगार सहायक उन्हें पीएम आवास की राशि रिलीज करने के नाम पर 500 रुपये से 6000 रुपये तक की राशि ले चुका है। महिला हितग्राही ने ये भी बताया कि पैसे लेने के बाद रोजगार सहायक ने उससे कोरे कागज पर साइन भी कराया।

प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़ा का ये आरोप ग्राम हरेठी के लोगों ने लगाया है। गांव वालों ने इसकी शिकायत कलेक्ट्रेट में भी की है। जिसके बाद मामले में जांच अभी पेंडिंग है। गांव वालों ने खुले तौर पर कहा है कि रोजगार सहायक अजय बरेठी ने उनसे रुपयों की मांग की। साथ ही रुपये नहीं देने पर पीएम आवास की किस्त आने में देरी होने की बात बताई। ग्रामीणों ने ये भी बताया कि रोजगार सहायक, अधिकारियों को पैसे देना है बोलकर उनसे पैसे मांगता था।

शिकायतकर्ता जय कुमार खैरवार ने कहा कलेक्टर ऑफिस में मैंने शिकायत की थी कि हरेटी गांव में रोजगार सहायक ने पुराने घर को जियो टैग कर नया घर बताकर गबन किया है। इसके बदले घर वालों से मोटी रकम ली गई। जिसके बाद जांच के लिए दो अधिकारी आए।

हितग्राही जगन्नाथ खैरवार ने कहा प्रधानमंत्री आवास की किस्त मिली थी। जिसके बाद रोजगार सहायक ने पैसे मांगे। 6000 रुपये किस्त में दिए, कहा अधिकारी को देना है। एक किस्त अभी मिलना बाकी है।

हितग्राही बुधवारा बाई ने कहा रोजगार सहायक अजय बरेठ ने घर की फोटो खींची और 500 रुपये मांगे। मैंने उससे कहा कि अभी पैसे नहीं है लेकिन वो पैसे तुरंत मांगने लगे। जिसके बाद यहां वहां से जुगाड़ कर उसे 500 रुपये दी हूं। तीन चार दिन के बाद कोरा कागज पर दस्तखत कराया।

ग्राम हरेठी सरपंच तुलेश जायसवाल ने कहा गांव के व्यक्ति ने कलेक्ट्रेट में शिकायत की है कि रोजगार सहायक पुराने घर को नया बताकर पैसे का गबन कर रहा है। जांच में आरोप सही पाए गए। जांच अधिकारी को दोषियों पर कार्रवाई करने की अपील की है।

जांच रिपोर्ट के इंतजार में वरिष्ठ अधिकारी- सक्ती जनपद सीईओ प्रीति पवार ने इस मामले में हो रही कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हरेठी पंचायत में पीएम आवास में रोजगार सहायक अजय बरेठ पर गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की थी। इस मामले में टीम बनाकर जांच कराई गई है। जांच टीम की तरफ से रिपोर्ट मिलने के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन की अनदेखी का शिकार सुकमा का गोगुंडा गांव

■ मलेरिया से पखवाड़े भर में 10 आदिवासियों की हुई मौत

सुकमा। 2,200 से अधिक जनसंख्या वाला सुकमा जिले का गोगुंडा गांव आज भी बुनियादी सेवाओं के लिए तरस रहा है। नक्सली दहशत और दुर्गम पहाड़ी इलाका में बसा यह गांव बीते 15 दिनों में 10 आदिवासियों की मौत के बाद चर्चा में है।

गोगुंडा हमेशा से मलेरिया हाई-रिस्क जोन रहा है। 2018 में यहां 350 से अधिक मलेरिया के मामले सामने आए थे, जो 2020 में बढ़कर 587 तक पहुंच गया। इसके बावजूद प्रशासन ने कभी भी इस क्षेत्र पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम है कि बीते 15 दिनों में 10 आदिवासियों की मलेरिया से मौत हो गई। अब खानापूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची है।

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब तक 400 ग्रामीणों की जांच की, जिनमें 158 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें 43 बच्चे भी शामिल हैं। हालत देखिए स्वास्थ्य अमले के पास केवल मलेरिया जांच की आरडी किट है। अन्य बीमारियों की जांच के लिए कोई सुविधा नहीं है। मरीजों को लक्षण के आधार पर ही दवाइयां दी जा रही हैं। अगर कोई अन्य बीमारी ग्रामीणों को हुई, तो काफी खतरनाक साबित हो सकती है।

मलेरिया से ग्रामीणों की मौत महज एक उदाहरण है गोगुंडा गांव के प्रति प्रशासन की उदासीनता का। गोगुंडा की स्थिति प्रशासन की असफलता की कहानी बयां करती है। नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में केवल खानापूर्ति नहीं बल्कि ठोस और निरंतर प्रयासों की जरूरत है। क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी या गोगुंडा जैसे गांव इसी हाल में रहने को मजबूर रहेंगे? गांव तक पहुंचने के लिए 8 किमी लंबी खड़ी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। राशन और दवाइयां पहुंचाने में ग्रामीणों की मदद ली जा रही हैस लेकिन पर्याप्त दवाइयों की कमी से इलाज प्रभावित हो रहा है। गांव में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। गांव में हैंडपंप तक नहीं हैं। ग्रामीण खुद एक दर्जन से अधिक रिंग कुएं बनाकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। क्रेडा विभाग द्वारा लगाए गए सोलर लाइट्स खराब हो चुके हैं। ऐसे में गांव में शाम 6 बजे के बाद घना अंधेरा छा जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं हैं। मात्र 6 कर्मचारी बड़ी आबादी के इलाज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। गोगुंडा नक्सली गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। गांव में प्रशासन की अन्य योजनाएं पहुंच ही नहीं पातीं स्वास्थ्य केंद्र की दीवारों पर सरकार के विरोधी नारे लिखे गए हैं, जो स्पष्ट संकेत देते हैं कि यह इलाका प्रशासन की पकड़ से बाहर है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए स्थायी समाधान की जरूरत है। उन्हें नियमित स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत सुविधाएं और नक्सल भय से मुक्त जीवन चाहिए।

पहले बारदाना लाओ, फिर होगी धान की खरीदी

बलौदा बाजार। जिले के 166 सेवा सहकारी समितियों के धान खरीदी केंद्रों में धान की खरीदी जारी है। किसानों से इस बार बार भी 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से लगभग 9 लाख 62 हजार 910 मैट्रिक टन धान की खरीदी होगी। अधिकतर खरीदी केंद्रों में पुराने बारदाने की कमी हो रही है। कई जगह सोमवार को जो किसान धान लेकर मंडियों में पहुंचे है। उन किसानों से 50 प्रतिशत बारदाना मंगाया जा रहा है। केंद्रों में बारदाना की कमी देखी जा रही है। इसको लेकर जिला बलौदा बाजार के आधा दर्जन से अधिक समितियां में जाकर देखा वहां प्रभारी द्वारा बताया गया कि पुराने बारदाना की कमी के चलते हम किसानों से 50 फीसदी बारदाना लाने को कह रहे हैं। तभी खरीदी हो पाएगी। इसकी समस्या की मुख्य वजह यह है कि मिलर की हड़ताल के चलते कस्टम मिलिंग में जो धान गया है। वहां से बारदाना वापस सोसाइटी में अभी तक नहीं पहुंचा है। वहीं धान खरीदने के लिए 50-50 का रेशों रखा गया है। मतलब 50 फीसदी नए बारदाने में खरीदी होगी और 50 फीसदी पुराने में होगी।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

एमपी-सीजी बॉर्डर पर बाघिन की एंट्री, ग्रामीणों में हड़कंप

कबीरधाम। एमपी-सीजी बॉर्डर पर हाथी के बाद अब बाघिन की एंट्री हो गई है। इस क्षेत्र में सीजी के कबीरधाम व एमपी के डिंडौरी, बालाघाट व मंडला जिला आता है। क्षेत्र में हाथी व बाघिन की एंट्री हुई है। ये कभी सीजी के कबीरधाम जिला तो कभी एमपी के डिंडौरी जिले के जंगल में आ जाते है। ऐसे में दोनों राज्य के वन विभाग की टीम हाई अलर्ट पर है। ग्रामीणों को जंगल में जाने की मनाही कर दी है। इस बीच एमपी के सिलपीडी के जंगल से ठाडपथरा बाघिन की तस्वीर ट्रैप कैमरा में कैद हुई है। बताया जा रहा कि एक दिन पहले ये डिंडौरी जिले के वन परिक्षेत्र दक्षिण समनापुर के रंजरा और बंजरा वन ग्राम में मौजूद थी। इसके बाद इसका मूवमेंट पश्चिम करंजिया रेंज अंतर्गत वन ग्राम ठाडपथरा के आसपास रहा है। इस दौरान बाघिन ने बस्ती के अंदर सड़क किनारे एक मवेशी का शिकार कर उसे घसीटते हुए गांव के बाहर ले गई। वर्तमान समय में इसका फिक्स लोकेशन नहीं मिल रहा है। ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की तरफ से आई है। इसी प्रकार सीजी के क्षेत्र में चार हाथी पंडरीपानी जंगल के क्षेत्र के मौजूद है।

एक साल बाद पकड़ा गया चोर गहने खरीदने वाले भी पकड़ाया

बेमेतरा। बेमेतरा पुलिस ने एक साल बाद चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही चोरी के गहने खरीदी करने वाले भी गिरफ्तार किए गए है। मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली थाना का है। थाना प्रभारी राकेश साहू ने बताया कि 18 अगस्त 2023 को प्रार्थी निखिल कुमार सोनी पिता भुपेन्द्र कुमार सोनी उम्र 39 वर्ष निवासी वार्ड नंबर चार रेस्ट हाउस चौक बेमेतरा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने अपने आवेदन में बताया कि उनके घर से 70 हजार रुपए कीमत के गहने, 8 हजार कीमत के मोबाइल व 10 हजार रुपए नगदी रकम चोरी है। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच जारी थी। इसी दौरान 23-24 नवंबर की मध्यरात्रि में गस्त के दौरान संदेही अविनाश मानिकपुरी निवासी सिमगा जिला बलौदाबाजार शहर में घूमते मिला। इससे पूछताछ करने पर पता चला कि पूर्व में चोरी करता था। चोरी के सामान को अजयपाल पिता अशोक कुमार पाल व राकु ऊर्फ राकेश चौहान पिता स्व.बैसाखु चौहान दोनों निवासी सिमगा जिला बलौदाबाजार बेचना बताया।

कार चालक ने डॉग पर चढ़ाई गाड़ी, एफआईआर दर्ज

दुर्ग। भिलाई में पशु क्रूरता का मामला सामने आया है। यहां एक एसयूवी चालक ने कार से स्ट्रीट डॉग को रौंद दिया और फिर उसे काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया और उसे तड़पता छोड़कर भाग गया। जब लोगों ने उसे देखा तो तत्काल डॉग को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन इलाज के दो घंटे के अंदर ही उसकी मौत हो गई। डॉग लवर लाभेश घोष ने कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। यह घटना रविवार शाम की है। जुनवानी रोड और डीमार्ट बायपास को जोड़ने वाली सड़क पर एक स्ट्रीट डॉग डिवाइडर के किनारे सो रहा था। इसी दौरान एक कार चालक ने अपनी गाड़ी कुत्ते के ऊपर चढ़ा दी। इससे कुत्ता कार के अगले पहिए में फंस गया, लेकिन चालक ने गाड़ी नहीं रोकी। वो कुत्ते को 500 मीटर तक घसीटते ले गया और फिर गाड़ी रोककर उसे बाहर निकाला। इसके बाद उसे वहीं तड़पता छोड़कर भाग गया। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कुत्ते को इलाज के लिए ले गए।

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर परिवहन संघ

बालोद। रेलमार्ग परिवहन के 40% हिस्सा में ट्रांसपोर्टिंग समेत पांच सूत्रीय मांग को लेकर राजहरा परिवहन संघ ने बीएसपी माइंस की गाड़ियों को रोककर चक्काजाम कर दिया है। बीएसपी अधिकारियों के साथ बैठक के बाद भी सहमति नहीं बनने पर परिवहन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चला गया है। परिवहन संघ के अध्यक्ष नरेन्द्र तुली, अजय अग्रवाल, सुनील जयसवाल, अनिल सुथार, संतोष देवांगन, गोविन्द वाधवानी, रवि जयसवाल, सुरजीत पन्नू, दमन दीप, संतोष कोशी के साथ राजहरा परिवहन संघ के सैकड़ों लोग धरने पर बैठे हैं। प्रमुख मांगों में रेलमार्ग से 100% परिवहन का 40% का परिवहन का कार्य दल्लीराजहरा से भिलाई तक दल्लीराजहरा परिवहन संस्था के मालवाहकों को दिया जाए। वर्तमान में हितेकसा में निर्माणाधीन पैलेट प्लांट से निर्मित होने वाले पैलेट का परिवहन कार्य दिया जाए। बीएसपी प्रबंधन द्वारा निजी क्षेत्र को बेची जाने वाली अनुपयोगी लौह अयस्क का परिवहन कार्य दिया जाए।

भतीजे ने ताऊ पर पेट्रोल डालकर लगाई आग

जगदलपुर। बस्तर जिले के नगरनार थाना क्षेत्र के ग्राम तारगुड़ा में रहने वाले एक भतीजे ने अपने बड़े पिता के घर मे देर रात को घुसकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, इस घटना के बाद घर में मौजूद परिजनों ने घायल को बेहतर उपचार के लिए मेकाज में भर्ती किया है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए नगरनार पुलिस ने बताया कि धारा 332(बी), 109 बीएनएस के तहत प्रार्थी लखमू राम कश्यप पिता स्व. झितरू कश्यप 60 वर्ष निवासी ग्राम उलनार पंचायत तारागुडा पारा नगरनार के 22 व 23 नवंबर के रात्री 12 बजे ग्राम उलनार पंचायत तारागुडा पारा प्रार्थी के घर मे घुसकर आरोपी शिबो कश्यप पिता विक्रम कश्यप 35 वर्ष निवासी ग्राम उलनार पंचायत तारागुडा पारा के द्वारा पेट्रोल डालकर आग लगा मौके से फरार हो गया। परिजनों ने बताया कि शिबो कश्यप के द्वारा प्रार्थी के हिस्से की जमीन को हड़पना चाहता है, जिसे लेकर आरोपी के द्वारा लखमू को जान से मारने की धमकी भी दिया था, 22 व 23 नवंबर को पीड़ित अपनी पत्नि के साथ घर में अकेला था।

सड़क हादसे में युवक की मौत, परिजनों ने किया चक्काजाम

■ वाहनों की लगी लंबी कतार

रायगढ़। रायगढ़ जिले में शनिवार की देर रात अज्ञात वाहन के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए युवक को अपनी चपेट में ले लिया था। जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई थी। इस घटना के बाद मृतक के परिजनों ने रविवार शाम साढ़े 5 बजे से चक्काजाम शुरू कर दिया था जो कि सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे समाप्त हुआ।

मिली जानकारी के मुताबिक तमनार थाना क्षेत्र के हुंकराडिपा चैक में शनिवार की रात सड़क हादसे में युवक की मौत हो जाने के बाद परिजनों के द्वारा आरोपी वाहन चालक की गिरफ्तार के अलावा मुआवजे की मांग को लेकर रविवार शाम साढे 5 बजे से चक्काजाम शुरू कर दिया गया था। इस मामले की जानकारी लगते ही तहसीलदार और थाना प्रभारी रविवार रात मौके पर पहुंचकर मृतक के परिजनों को समझाइस देते हुए तत्कालिक सहायता राशि के रूप में 75 हजार देने के लिए प्रशासन द्वारा परिजनों से बात भी की गई, लेकिन परिजन उचित मुआवजे की मांग को लेकर अड़े हुए थे। हुंकराडीपा चैक में चक्काजाम की जानकारी मिलते ही लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र की विधायक विद्यावती सिदार भी मौके पर पहुंची और काफी समय तक परिजनों के साथ घटना स्थल पर बैठी रहीं फिर चली गई थी और आज सुबह फिर से मौके पर पहुंची थी।

लैलूंगा विधानसभा की विधायक विद्यावती सिदार ने बताया कि हुंकराडीपा चैक में शनिवार की देर रात अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। शाम के समय मृतक की शिनाख्त होनें के बाद परिजनों ने चक्काजाम शुरू कर दिया। शासन-प्रशासन के द्वारा मौके पर पहुंचकर आज चक्काजाम समाप्त कराया गया है। परिजनों को 1 लाख 25 हजार और क्लेम होनें के बाद 2 लाख रूपये देने का फैसला लिया गया है।

पुलिस अधिकारी अभिनव उपाध्याय ने बताया कि शनिवार की रात अज्ञात वाहन की ठोकर से एक युवक की मौत हो जाने के बाद प्रारंभिक जांच में मृतक की शिनाख्त जतन कुमार सारथी 33 साल के रूप में की गई, जो जशपुर का रहने वाला है और बीते कुछ समय से अपने ससुराल बांधापाली में रहते हुए गाड़ी चलाने का काम करता था। मृतक की शिनाख्त होते ही पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना से अवगत कराया था लेकिन मृतक के परिजन मुआवजे की मांग को लेकर हुकराडीपा चैक में चक्काजाम शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों को समझाईश देकर चक्काजाम समाप्त कराया गया है।

सड़क हादसे में युवक की मौत हो जाने के बाद मृतक के परिजनों ने रविवार शाम साढ़े 5 बजे से चक्काजाम शुरू किया गया था जो कि सोमवार दोपहर साढ़े 12 बजे समाप्त हुआ। इस दौरान इस क्षेत्र में स्थापित कंपनियों के अलावा कोयला खदानों में चलने वाली सभी गाड़ियों के पहिये पूरी तरह थम गए थे और वाहनों की लंबी कतार लग गई थी। आज परिजनों को मुआवजा देने के पश्चात यह चक्काजाम समाप्त हुआ तब जाकर वाहनों का परिचालन शुरू हो सका।

भारत फाइनेंस कंपनी में करीब 38 लाख का गबन

फरार आरोपी एक साल बाद गिरफ्तार

रामानुजगंज। भारत फाइनेंस कंपनी में गबन के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को रामानुजगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने कंपनी में काम करते हुए 37 लाख 99 हजार रुपये का गबन किया था और पिछले एक साल से अलग-अलग स्थानों पर छिपा हुआ था।

जानकारी के अनुसार, भारत फाइनेंस इनक्लूजन लिमिटेड में कार्यरत सुरेंद्र दास (24 वर्ष) ने अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर बैंक से ग्राहकों को मिलने वाली रकम और जमा राशि का गबन कर उसे अपने व्यक्तिगत उपयोग में खर्च किया। इस मामले में रामानुजगंज थाने में धारा 409 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

मामले में जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र के तीन अन्य साथियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। सुरेंद्र दास, जो सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र के अंचला माझापारा गांव का निवासी है, लंबे समय से फरार था। पुलिस को मुखबिर से सुरेंद्र की मौजूदगी की सूचना मिली, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने सुरेंद्र को विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए न्यायालय रामानुजगंज में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

पिछले साल के इसी अवधि के तुलना में अपराधों में 3 प्रतिशत की आंशिक कमी

रायपुर। आईजीपी रायपुर अमरेश मिश्रा और

एसएसपी संतोष सिंह के निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां, बदमाशों व अड्डेबाजी पर कार्यवाही, विजिबल पुलिसिंग और नशे के खिलाफ कार्यवाहियों पर जोर दिया जा रहा है। जिला रायपुर में माह फरवरी से अब तक आईपीसी/बीएनएस के तहत 7970 अपराध दर्ज किए गए हैं। पिछले साल इसी अवधि में 8224 अपराध दर्ज हुए थे। इस तुलनात्मक अवधि में अपराधों में 3 प्रतिशत की आंशिक कमी हुई है। पिछले साल चाकूबाजी की 171 की जगह 102 घटनाएं और हत्या के 54 की बजाय 58 घटनाएं हुई हैं। चाकूबाजी में 40 फीसदी की कमी, हत्या में 7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है। छेड़छाड़/यौन हिंसा में 28 फीसदी, बलात्कार में 8 फीसदी, चोरी में 9 और मारपीट में 3 प्रतिशत की कमी है। इस वर्ष माह फरवरी से चलाए जा रहे नशे के खिलाफ निजात अभियान के कारण एनडीपीएस व आबकारी के दर्ज प्रकरणों में तेजी के कारण कुल पंजीबद्ध अपराध में बढ़ोतरी परिलक्षित हो रही हैं।

साय कैबिनेट की बैठक 26 को, महत्वपूर्ण विषयों पर लग सकती है मुहर

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक 26 नवंबर को दोपहर 12 बजे मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में आयोजित की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। पांच दिन के सत्र में होने वाली चार बैठकों में सरकार कुछ अहम विधेयक पास करा सकती है, जबकि कई अहम मुद्दों पर विधानसभा सत्र में चर्चा होगी। इस लिहाज से साय कैबिनेट की बैठक में पास कराए जाने वाले विधेयक पर निर्णय ले सकती है।

कौटिल्य एकेडमी के नाम पर यूपीएससी-पीएससी कोचिंग के नाम पर ठगी

रायपुर। कौटिल्य एकेडमी के नाम पर यूपीएससी-पीएससी कोचिंग के लिए छात्रों से 18 लाख रुपए ठगने का मामला सामने आया है। कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर पवन टांडेश्वर और उनकी पत्नी रूबी मजूमदार फरार हो गए हैं। सरस्वती नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। कौटिल्य एकेडमी ने जीई रोड स्थित अनुपम गार्डन के सामने यूपीएससी-पीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर शुरू किया था। डायरेक्टर पवन टांडेश्वर और उनकी पत्नी ने करीब 18 छात्रों से 18 लाख रुपए की फीस ली। कुछ समय बाद शिफ्टिंग का बहाना बनाकर कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया। छात्रों और उनके पालकों ने बताया कि जब क्लास बंद हुई, तो डायरेक्टर ने अक्टूबर में नए स्थान पर क्लास चालू करने की बात कही लेकिन इसके बाद भी कोचिंग शुरू नहीं हुई। पुराने क्लास रूम पर भी ताला जड़ दिया गया। छात्रों ने जब संपर्क किया तो डायरेक्टर और उनकी पत्नी ने बातचीत से बचना शुरू कर दिया और कई छात्रों के नंबर ब्लैकलिस्ट कर दिए।

छत्तीसगढ़ के अमृत सरोवरों में कल मनाया जाएगा संविधान दिवस

रायपुर। संविधान अंगीकरण की स्मृति में 26 नवंबर को प्रति वर्ष देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस हमारे देश के लोकतांत्रिक ढांचे की आधारशिला के रूप में हमारे मूल्यों की याद दिलाता है। इस ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए राज्य के अमृत सरोवर स्थलों पर संविधान दिवस मनाया जाएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस संबंध में सभी कलेक्टरों को प्रदेश के अमृत सरोवर स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित कर संविधान दिवस मनाने तथा संविधान की प्रस्तावना का वाचन किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस ऐतिहासिक दिन को स्मरणीय बनाने के लिए अमृत सरोवर स्थलों पर एक विशेष समारोह का आयोजन करने प्रस्ताव किया है, जिसके तारतम्य में राज्य में स्थानीय समुदायों, अमृत सरोवर उपयोगकर्ता समूहों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी में संविधान दिवस मनाया जाएगा। संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन अमृत सरोवर स्थलों में प्रातः 11 बजे संविधान की प्रस्तावना का पठन होगा, जिसमें संविधान के आदर्शों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया जाएगा। स्थानीय हितधारकों, समूहों और शासकीय अधिकारियों को शामिल होकर संविधान दिवस का व्यापक और प्रभावी आयोजन किया जावेगा।

महंत कॉलेज में मनाया गया कौमी एकता दिवस

रायपुर। महंत लक्ष्मी नारायण दास महाविद्यालय रायपुर में देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जन्म तिथि के उपलक्ष में आज कौमी एकता दिवस मनाया गया इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी ने छात्र-छात्राओं को धर्मनिरपेक्षता और भाईचारे की शपथ दिलाई। वही कार्यक्रम में काफी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी ने छात्र-छात्राओं को शपथ दिलाते हुए अनेकता में एकता धर्मनिरपेक्षता की जानकारी दी और बताया कि जब देश विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है। ऐसी स्थिति में हम सभी को हमारे पूर्वज और राष्ट्रीय नेताओं के योगदान को आत्मसात करते हुए नई दिशा में बढ़ाना चाहिए।

नई औद्योगिक नीति से प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातारण का निर्माण होगा : मंत्री देवांगन

■ **31 मार्च 2030 तक के लिए होगी नई औद्योगिक नीति**

रायपुर। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि प्रदेश की नवीन औद्योगिक नीति में उद्यमियों एवं युवाओं के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने वाली है। इससे प्रदेश में बेहतर औद्योगिक वातारण का निर्माण होगा और प्रदेश के निवासियों को रोजगार उपलब्ध होंगे। ज्ञात हो कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा 14 नवम्बर को प्रदेश में नवीन औद्योगिक नीति लॉन्च की गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत सरकार के विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने तथा राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से कई प्रावधान किए हैं। राज्य के प्रशिक्षित व्यक्तियों को औपचारिक रोजगार में परिवर्तित करने के लिए उद्योगों हेतु प्रति व्यक्ति 15 हजार रूपए की प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। यह नीति 31 मार्च 2030 तक के लिए होगी।

उद्योग मंत्री श्री देवांगन ने बताया कि नई औद्योगिक नीति में निवेश प्रोत्साहन में ब्याज अनुदान, लागत पूंजी अनुदान, स्टाम्प शुल्क छूट, विद्युत शुल्क छूट. मूल्य संवर्धित कर प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। नई नीति में

मंडी शुल्क छूट, दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान, पर्यावरणीय प्रोजेक्ट अनुदान, परिवहन अनुदान, नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर की प्रतिपूर्ति के भी प्रावधान किये गये हैं।

इस नीति में राज्य के युवाओं के लिये रोजगार सृजन को लक्ष्य में रखकर एक हजार से अधिक स्थानीय रोजगार सृजन के आधार पर बी-स्पोक पैकेज विशिष्ट क्षेत्र के उद्योगों के लिये प्रावधानित है। राज्य के निवासियों विशेषकर अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्यमियों, सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, भूतपूर्व सैनिकों, जिनमें पैरामिलिट्री भी शामिल है, को नई औद्योगिक नीति के तहत अधिक प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है। नक्सल प्रभावित लोगों, कमजोर वर्ग, तृतीय लिंग के उद्यमियों के लिए नई औद्योगिक पॉलिसी के तहत विशेष प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया है। नई औद्योगिक नीति में पहली बार सेवा क्षेत्र अंतर्गत एमएसएमई सेवा उद्यम एवं वृहद सेवा उद्यमों के लिये पृथक-पृथक प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

इस नीति में फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाईल, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण तथा गैर काष्ठ वनोत्पाद (एनटीएफपी) प्रसंस्करण, कम्प्रेस्ड बॉयो गैस, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, आर्टिफिशियल इंटीलिजेंस (ए.आई), रोबोटिक्स एण्ड कम्प्यूटिंग (जी.पी.यू), आई.टी., आई.टी.ई.एस., डेटा सेंटर, जल विद्युत परियोजनाओं, सौर ऊर्जा परियोजनाओं आदि के लिए आकर्षक पृथक औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का प्रावधान है। राज्य के कोरबा-बिलासपुर-रायपुर को देश के औद्योगिक मानचित्र में स्थान दिलाने के लिये इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर की स्थापना का प्रावधान है। नई औद्योगिक नीति के निर्माण के लिए उद्योग विभाग द्वारा संबंधित सभी हितपक्षों, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक समूहों, संबंधित विभागों के साथ एक वर्ष तक संवाद एवं गहन विचार-विमर्श कर तैयार किया गया है।

अस्पताल से कृषि मंत्री रामविचार नेताम का ट्वीट

आपकी दुआओं ने किया संजीवनी जैसा काम

रायपुर। बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम बीते दिनों सड़क हादसे में घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उनको रायपुर लाया गया। रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के मुताबिक रामविचार नेताम की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक वो जल्द ही पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। तेजी से रिकवर हो रहे मंत्री रामविचार नेताम ने ट्वीट कर लोगों का धन्यवाद दिया है। रामविचार नेताम ने कहा कि आप सबों के स्नेह और शुभकामनाओं से मेरे स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। आपकी दुआओं का असर मेरे लिए संजीवनी से कम नहीं है।

अपने ट्वीट में कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि भयानक हादसे के बाद मेरे स्वास्थ्य में तेजी से सुधार हो रहा है। अपने ट्वीट में नेताम ने कहा कि आपका आशीर्वाद और आपकी मंगलकामनाएं मेरी असली शक्ति हैं। मुश्किल पलों में जिस तरह से जनता और साथियों ने मेरा हौसला बढ़ाया वो मेरे लिए प्रेरणादायक है। आप सब मेरे साथ रहे इसलिए मुझे इस मुश्किल घड़ी में कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। मैं सभी साथियों, मेरे चाहने वालों के प्रति आभार जताता हूं।

रामविचार नेताम ने कहा गिरकर उठना ही जिंदगी की पहचान है, हर मुश्किल के बाद एक नई उड़ान है।

22 नवंबर को प्रदेश के कृषि मंत्री बेमेतरा दौरे पर थे। सर्किट हाउस में बीजेपी नेताओं और प्रशासनिक अफसरों के मुलाकात के बाद वो रायपुर लौट रहे थे। रायपुर लौटने के दौरान उनकी गाड़ी पिकअप वाहन से टकरा गई। टक्कर आमने सामने की हुई थी। जिस गाड़ी में मंत्री सवार थे उस गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से छतिग्रस्त हो गया था। हादसे के बाद तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मंत्री और बाकी

टामन-श्रवण को सीबीआई कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल

रायपुर। सीजीपीएससी घोटाला छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित मामलों में से एक है। सोमवार को सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और श्रवण गोयल को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। इस विशेष अदालत ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

सीबीआई ने दोनों आरोपियों को 18 नवंबर को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें 19 नवंबर को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। दोनों को 7 दिनों की रिमांड पर सीबीआई को सौंपा गया था। इन सात दिनों में सीबीआई ने दोनों आरोपियों से सीजीपीएससी घोटाले केस के संबंध में पूछताछ की। अब दोबारा रिमांड पर भेजे जाने के बाद दोनों आरोपी रायपुर सेंट्रल जेल में 14 दिनों तक रहेंगे। इसके बाद फिर से कोर्ट में पेशी के लिए उपस्थित होंगे।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा साल 2019 से 2022 तक कुछ अभ्यर्थियों के चयन को लेकर विवाद सामने आया था। जिसके बाद ईओडब्ल्यू और अर्जुंदा पुलिस ने भ्रष्टाचार व अनियमितता का केस दर्ज किया था। साल 2020 में 175 पदों पर और साल 2021 में 171 पदों पर परीक्षा ली थी। सीजीपीएससी के इसी भर्ती को लेकर विवाद की स्थिति बनी थी। सीजीपीएससी के तात्कालिन अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पर अपने रिश्तेदारों सहित कांग्रेसी नेता और ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों की नौकरी लगवाने का आरोप है।

आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़ रहा है छत्तीसगढ़: प्रमुख सचिव

रायपुर। राजधानी के निजी होटल में आज इमर्जिंग टेक्नेलॉजी की जानकारी से अवगत कराने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। भारत सरकार की संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्प्यूटिंग (सी-डेक) की ओर से आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक ने छत्तीसगढ़ में आईटी क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी।

कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को संबोधित करते हुए निहारिका बारिक ने कहा कि तकनीक हर पल बदल रही है। ऐसे में शासन के समक्ष इन उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ कदम मिलाकर चलना एक गंभीर चुनौती है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इन चुनौतियों से पार पाने और उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ समन्वय करने के लिए राज्य में डिजिटल अधोसंरचना विकास, ई-सुशासन, साइबर सुरक्ष, डिजिटल साक्षरता, कौशल विकास और आईटी उद्योगों को प्रोत्साहन आदि अनेक प्रमुख क्षेत्रों को चिन्हित कर प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है।

छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात

मलिक ने चिप्स की स्थापना का उद्देश्य बताते हुए कहा कि राज्य में आईटी अधोसंरचना का विकास करना चिप्स का प्रमुख लक्ष्य है। चिप्स द्वारा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टेट डाटा सेंटर विकसित किया गया है। शासकीय संस्थाओं को आपस में सुरक्षित रूप से जोड़ने के लिए सीजी स्वान परियोजना का संचालन किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य के विभागों को उनकी आवश्यकता के अनुसार तकनीकी सहयोग भी चिप्स द्वारा प्रदान किया जाता है। साथ ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए निकट भविष्य में चिप्स द्वारा कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि उच्च स्तर पर निर्णयकर्ताओं के साथ-साथ राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों की क्षमता विकास किया जा सके।

सी-डेक की वरिष्ठ निदेशक डॉ. पद्मा जोशी ने अतिथियों को धन्यवाद देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार सी-डेक द्वारा कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इमर्जिंग टेक्नालाजी, ब्लॉकचेन, आधार प्रमाणीकरण जैसी आधुनिक तकनीकों के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉ. पद्मा जोशी ने कहा कि ऐसे कार्यशालाओं के आयोजन से आईटी क्षेत्र में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा सकता हैद्ध कार्यक्रम में चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मलिक साथ-साथ आईएसबीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ। आनंद मलावार, सी-डेक मुंबई से वीणा त्यागी, राजीव श्रीवास्तव, निर्मला सलाम और चिप्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार बिश्व रंजन भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अयोध्या धाम के लिए रायपुर से 850 श्रद्धालु हुए रवाना

श्री रामलला दर्शन योजना, भक्तों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सरकार द्वारा शुरू की गई श्रीरामलला दर्शन योजना को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह का माहौल है। रायपुर संभाग के 850 श्रद्धालुओं को लेकर आज विशेष ट्रेन अध्योध्या धाम के लिए रवाना हुई। इस विशेष ट्रेन को खाद्य मंत्री दयालदास बघेल एवं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा एवं विधायक पुरेंदर मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया।

अध्योध्या धाम के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं का रायपुर स्टेशन में भव्य स्वागत किया गया। गाजे-बाजे और पारंपरिक नृत्य से उनका स्वागत हुआ। ये श्रद्धालु काशी विश्वनाथ का भी दर्शन करेंगे। रायपुर रेलवे स्टेशन पर भजन गाते हुए विशेष ट्रेन में सवार होकर यात्री रवाना हुए। सभी श्रद्धालुओं की रामलला के दर्शन की अभिलाष भी पूरी होने जा रही है। ये श्रद्धालु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति दिल से आभार व्यक्त किया। श्रद्धालुओं का कहना था कि मुख्यमंत्री ने अपना वादा निभाया है

और सरकार की श्री रामला दर्शन योजना से अयोध्या जाने की उनकी इच्छा पूरी हो रही है। यह उनका सौभाग्य है। आरंग निवासी हरिश साहू, महेश देवांगन, गुलाबा देवांगन, बलौदाबाजार निवासी बिसाबाई कन्नौजे, कसडोल निवासी दरशराम वर्मा एवं खोरबहार भी अयोध्या रामलला दर्शन के लिए जा रहे है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार जताया। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराकर सरकार पुण्य का काम कर रही है। उम्र के इस पड़ाव में सभी को तीर्थ यात्रा की इच्छा रहती है, लेकिन आर्थिक कठिनाईयों के चलते संभव नहीं हो पाता है। हम सरकार के आभारी है कि उन्होंने हमारी ये इच्छा पूरी की।

उल्लेखनीय है कि श्री रामलला दर्शन योजना के तहत श्रद्धालुओं को छत्तीसगढ़ से अयोध्या जाने, वहां ठहरने की व्यवस्था, मंदिर दर्शन, नाश्ते, खाने की भी व्यवस्था रहेगी। इस ट्रेन में टूर एस्कॉर्ट, सुरक्षाकर्मी और चिकित्सकों का दल भी मौजूद रहेगा। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर अबिनाश मिश्रा, संयुक्त कलेक्टर उमाशंकर बंदे, जिला पंचायत अतिरिक्त सीईओ हरिकृष्ण जोशी भी उपस्थित थे।

कांग्रेस चलाएगी 26 नवंबर से 26 जनवरी तक संविधान रक्षक अभियान

रायपुर। कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा के लिये आगामी 26 नवंबर 2024 से 26 जनवरी 2025 तक 60 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हमेशा हमारे संविधान में निहित मूल्यों की रक्षा के लिए खड़ी रही है। पिछले दशक में भाजपा नेतृत्व वाली सरकार द्वारा संविधान की नींव को कमजोर करने और सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को कमजोर करने के व्यवस्थित प्रयास किया है।

बैज ने कहा कि इस 60 दिवसीय संविधान रक्षक अभियान में पांच प्रमुख विषयों को आमजनता के समक्ष उजागर किया जाना है प्रत्येक विषय के लिये 10 दिवसीय अवधि तथा 5 विषय निर्धारित किये गये है।

भारत में असमानता और इसे संबोधित करने में भाजपा की केंद्र सरकार की विफलता को उजागर किया जाये। एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों, गैर-अधिसूचित जनजातियों, महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं पर विशेष ध्यान देने के साथ, हाशिए पर रहने वाले समुदायों की स्थिति खराब करने वाली नीतियों को उजागर किया जायेगा।

जाति जनगणना की वकालत व आरक्षण व्यवस्था पर भाजपा के हमलों और उनकी भेदभावपूर्ण विचारधारा को उजागर किया जायेगा।

अल्पसंख्यकों, एससी, एसटी और ओबीसी को निशाना बनाने वाली भाजपा की विभाजनकारी राजनीति का उजागर करेंगे। भाजपा के व्यवस्थित भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले डेटा सार्वजनिक और व्याख्यान आयोजित होगा।

आम लोगों की कीमत पर कुछ पूंजीपतियों के प्रति भाजपा की पक्षपात को उजागर करेंगे। भाजपा के शासन में बढ़ी आर्थिक असमानता पर प्रकाश डाला जायेगा।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एजेंसियों के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मूल्यों के क्षरण पर भाजपा के हमलों को संबोधित करें।भाजपा को अधिनायकवादी राज्य बनने से बचाने की आवश्यकता पर जोर देंगें।

महाविद्यालय की सरकारी जमीन बिल्डर को आबंटित, ग्रामीण आज देंगे केनाल रोड में धरना

रायपुर। अमलीडीह में शासकीय नवीन महाविद्यालय के लिए आरक्षित करीब 9 एकड़ सरकारी जमीन को रामा बिल्डकॉन को आबंटित कर दी गई। यह पूरी प्रक्रिया गुपचुप तरीके से हुई है और अब जमीन आबंटन की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने तत्काल आबंटन निरस्त करने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा है लेकिन अभी तक जमीन का आबंटन निरस्त नहीं किया गया है। अब ग्रामीण हमर माटी हमर भुईयां रक्षा समिति अमलीडीह के बैनर तले सांकेतिक रुप से मंगलवार को अमलीडीह स्थित केनाल रोड में एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताएंगे।

कुर्मी समाज के लीलाधर चंद्राकर, हरदिहा साहू समाज के अध्यक्ष मन्ना राम साहू, सतनामी समाज के मंगलदास कोसरिया, यादव समाज के कन्हैया यादव, सेन समाज के देव कुमार जैन, छत्तीसगढ़ क्रांतिसेना के धीरेंद्र साहू ने संयुक्त पत्रकारवार्ता में बताया कि रायपुर नगर निगम सीमा के गांव अमलीडीह में 3.203 हेक्टेयर यानी करीब 9 एकड़ जमीन शासकीय नवीन महाविद्यालय के लिए आरक्षित की गई थी। कॉलेज अभी स्कूल बिल्डिंग में संचालित है। पिछली सरकार में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कॉलेज जमीन के लिए सरकारी जमीन आरक्षित कराई थी। इस जमीन पर बिल्डरों की भी नजर रही है और एक बड़े बिल्डर रामा बिल्डकॉन के संचालक राजेश अग्रवाल ने उस समय आरक्षित जमीन के आबंटन के लिए आवेदन किया था। न सिर्फ रामा बिल्डकॉन बल्कि

इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट ने भी उक्त जमीन के लिए आवेदन किया था। पिछली सरकार में सरकारी जमीन की नीलामी की नीति रही है। चूंकि कॉलेज बिल्डिंग-खेल मैदान के लिए आरक्षित होने की वजह से बिल्डर के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

सरकार बदलने के बाद प्रभावशाली लोगों ने बिल्डर को उक्त जमीन को आबंटित करने के लिए पहल की। इसके बाद इसका तोड़ निकालते हुए रामा बिल्डकॉन के पुराने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें आबंटित कर दी। यह आबंटन 28 जून को राजस्व विभाग ने किया है। खास बात यह है कि सब कुछ आबंटन पिछली सरकार की नीति के मुताबिक किया गया। सरकार बदलने के बाद सरकारी जमीन के आबंटन, और फ्रीहोल्ड संबंधी सभी निर्देशों को 11 जुलाई को निरस्त कर दिया गया। चर्चा है कि जमीन का आबंटन आदेश जारी होने से पहले बैक डेट में किया गया। कॉलेज की जमीन बिल्डर को आबंटित होने की खबर अब जाकर ग्रामीणों को हुई है, और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

पत्रकारों से चर्चा करते हुए लीलाधर ने बताया कि गांव में यही एक सरकारी जमीन बची थी जिस पर कॉलेज का निर्माण होना था। पिछली सरकार में विधायक सत्यनारायण शर्मा ने अस्पताल निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत कराई थी लेकिन सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण आगे कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। अब सरकारी जमीन को आबंटित करने के खिलाफ ग्रामीणों ने सडक़ की लड़ाई लडने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने इस सिलसिले में मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्रीऔर स्थानीय विधायक मोतीलाल साहू को ज्ञापन भी भेजा है। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया था कि इस मामले का जल्द ही पटाक्षेप हो जाएगा लेकिन अभी तक हुआ है। कल वे एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध जताएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यहां पर शासकीय नवीन कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द शुरु हो सकें।

महाराष्ट्र में सिर चढ़कर बोला मोदी की लोकप्रियता का जादू

कृष्णमोहन झा

महाराष्ट्र में सत्तारूढ महायुति ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर प्रमुख विपक्षी दलों कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एन सी पी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दरअसल इन तीनों पार्टियों ने यह मान लिया था कि जिस तरह पिछले लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उन्हें अपना व्यापक दिया था उसकी पुनरावृत्ति राज्य विधानसभा के चुनावों में होना बिल्कुल तय है लेकिन मतगणना के रुझानों में शुरू से ही महायुति ने अपनी बढ़त बनाने का जो सिलसिला प्रारंभ किया वह पूरी मतगणना के दौरान कभी भी बाधित नहीं हुआ और अंततः महायुति के पक्ष में जो जनादेश आया उसमें महाविकास अगाड़ी के घटक दलों को सदन के अंदर विपक्ष में बैठकर आत्ममंथन करने का संदेश छुपा हुआ था। महाविकास अगाड़ी के प्रमुख घटक दल शिवसेना (उद्धव ठाकरे) को महायुति की प्रचंड जीत ने हक्का बक्का कर दिया है। उसके प्रवक्ता संजय राऊत ने यहां तक कह दिया कि इन चुनाव परिणामों में कुछ तो गडबड है। यह महाराष्ट्र की जनता का फैसला हो ही नहीं सकता। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में मूल शिव सेना के कुछ विधायकों ने एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में पार्टी से बगावत कर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाई थी इसके अलावा शरद पवार की एनसीपी के कुछ विधायकों ने भी अजित पवार के नेतृत्व में पार्टी से विद्रोह कर महायुति सरकार में शामिल होने का फैसला किया था। इन चुनावों में शिव सेना (उद्धव ठाकरे) और एन सी पी(शरद पवार) यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की करिश्माई लोकप्रियता भी एकनाथ शिंदे और अजित पवार को महाराष्ट्र के मतदाताओं का कोपभाजन बनने से नहीं रोक पाएगी परंतु चुनाव परिणामों ने उन्हें एकदम सदमे की स्थिति में पहुंचा दिया है। चुनाव परिणामों में गड़बड़ी की आशंका व्यक्त करने वाले महाविकास अगाड़ी के घटक दलों को इस सवाल का जवाब अपने अंदर ही खोजना होगा कि लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने उन्हें जो समर्थन प्रदान किया था उस पर कायम रहने के लिए वे राज्य के मतदाताओं को राजी क्यों नहीं कर पाए। महाराष्ट्र विधानसभा के इन चुनावों में भाजपा ने अभूतपूर्व विजय प्राप्त कर इतिहास रच दिया है और स्वाभाविक रूप से अब वह महायुति सरकार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसका अधिकार होगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी की तुलना में दुगनी से भी अधिक सीटों पर जीत हासिल करने वाली भाजपा को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपने के लिए एक नाथ शिंदे को राजी करने में भाजपा को कोई दिक्कत पेश होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर भाजपा चाहेगी तो सत्ता में बने रहने के लिए एकनाथ शिंदे को यह त्याग अब खुशी खुशी करना होगा। राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस भी ऐसा ही उदाहरण पेश कर चुके हैं। अब यह उत्सुकता का विषय है कि महायुति की नयी सरकार का नेतृत्व करने का गौरव देवेन्द्र फडनवीस अर्जित करते हैं अथवा पार्टी उन्हें कोई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपती है लेकिन इसमें दो राय नहीं हो सकती कि महाराष्ट्र विधानसभा के इन चुनावों में भाजपा की प्रचंड जीत में देवेन्द्र फडनवीस ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महाराष्ट्र भाजपा के अंदर से यह मांग उठने भी लगी है। इन चुनाव परिणामों ने महाराष्ट्र की राजनीति में देवेन्द्र फडनवीस के कद को बहुत ऊंचा कर दिया है और पार्टी की प्रदेश राजनीति में उन्हें पार्टी के अंदर चुनौती देने का साहस कोई नहीं कर सकता। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी चुनाव जीत कर अपनी अहमियत दिखा दी है लेकिन महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों में भाजपा की सुनामी ने केवल विपक्ष ही नहीं, सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य दलों को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। गौरतलब है कि भाजपा ने 288 सदस्यीय विधानसभा की 149 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे जिनमें 127 उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में बढ़त बनाए हुए हैं। इस तरह उसका स्ट्राइक रेट 86 प्रतिशत है।यह अपने आप में एक कीर्तिमान है।

विधानसभा के चुनावों के निहितार्थ

उमेश चतुर्वेदी

हर राज्य की अपनी अहमियत है। लेकिन राजनीतिक लिहाज से देखें तो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी राज्य का है तो वह महाराष्ट्र है। देश की आर्थिक राजधानी इस राज्य की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के मुकाबले 48 सीटों के साथ दूसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। राजनीतिक हलकों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी होने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदा विपक्षी निशाने पर रहती है, उस संघ का मुख्यालय भी इसी राज्य में है। इस लिहाज से महाराष्ट्र के चुनाव नतीजों का असर दूरगामी होना स्वाभाविक है। मराठी मानुष ने जो जनादेश दिया है, उसका असर देश की राजनीति पर तो पड़ेगा ही, अर्थनीति पर भी पड़ेगा। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर भी कई बदलाव नजर आ सकते हैं। देश की राजनीति पर झारखंड के चुनाव नतीजों का भी पड़ना ही है। इसका असर दिखने लगा है। इंडिया गठबंधन की अगुआई राहुल गांधी से छीनने को लेकर आवाज उठने लगी है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मांग आ भी गई है कि मोदी को चुनौती देने के लिए जरूरी है कि इंडिया गठबंधन की कमान राहुल गांधी की बजाय ममता बनर्जी को दी जाय।

महाराष्ट्र के क्षत्रप शरद पवार को लेकर हाल ही में कहा जाने लगा था कि उनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। इस धारणा को ढाई साल पहले बीजेपी ने तोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे की अगुआई में शिवसेना में टूट हुई और सबसे ज्यादा 104 विधायक होने के बावजूद बीजेपी ने अपने कद्दावर नेता देवेंद्र फणनवीस को शिंदे का सहयोगी बनने के लिए राजी कर लिया। इस सरकार के कार्यकाल में हुआ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुआई वाली महायुति को समर्थन नहीं मिला। बीजेपी और शिवसेना-शिंदे- दोनों को लोकसभा सीटों का नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन इससे बीजेपी और शिवसेना दोनों ने सीख ली। बीजेपी ने अपने पारंपरिक गढ़ विदर्भ पर फोकस तो किया ही, गैर मराठा वोटरों पर भी अपना ध्यान लगाया। मराठवाड़ा में शिवसेना शिंदे और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर भरोसा जताया। नतीजा सामने है। पार्टी ने इस बीच एक काम और किया। उसने माझी लड़की बहीण योजना

लागू की। इसके तहत 21 से 65 साल तक की उम्र वाली पात्र महिलाओं को पंद्रह सौ रूपए महीने दिए जाने लगे हैं। राज्य की करीब एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने लगा है। इसका फायदा महाराष्ट्र की महायुति सरकार को हुआ है। माना जा रहा है कि राज्य की महिलाओं ने महायुति की अगुआई वाली सरकार को अपना समर्थन दिया है।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह कई अन्य राज्य सरकारें महिलाओं को आर्थिक सहयोग देना शुरू कर चुकी हैं। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र के नतीजों के बाद इस चलन को और बढ़ावा मिलेगा। बाकी राज्य सरकारें भी तेजी से इस दिशा में कदम बढ़ाएंगी और महिला वोटरों को रिझाने की कोशिश करेंगी। हालांकि झारखंड में एनडीए का यह फॉर्मूला नहीं चल पाया है। झारखंड की 81 में से 68 सीटों पर पुरूषों की तुलना में साढ़े पांच लाख से ज्यादा महिला वोटरों ने मतदान किया है। बीजेपी वहां के लिए ढाई हजार रूपए की माई सम्मान योजना का प्रस्ताव लेकर आई थी. लेकिन वहां की महिलाओं ने हेमंत सोरेन की गोगो दीदी योजना पर ही ज्यादा भरोसा जताया।

महाराष्ट्र के चुनावों का असर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ सकता है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में 13 सीटें जीतकर बड़ा दल बनने के बाद पार्टी ने ग्रेस सबसे बड़ा दल बनकर उभरी। इसके चलते पार्टी में गुरूर दिखने लगा। विधानसभा चुनावों के लिए सीट बंटवारे में पार्टी खुद को सबसे आगे रखने और सहयोगी दलों को पीछे रखने की रणनीति पर काम करने लगी। चुनाव नतीजे आने से पहले ही मुख्यमंत्री पद को लेकर जिस तरह खींचतान सामने आई, उससे साफ था कि कांग्रेस की अगुआई वाले गठबंधन में सबकुछ ठीक नहीं था। इसका असर चुनाव नतीजों पर साफ नजर आ रहा है। इसकी तुलना में झारखंड में पार्टी ने हेमंत की सहयोगी की भूमिका में रखा तो वहां के नतीजे अलग तरीके से आए। साफ है कि पार्टी जहां खुद का वर्चस्व रखती है, वहां उसे मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन जहां वह सहयोगी दलों की बैसाखी पर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, उसे फायदा होता है। साफ है कि आने वाले दिनों में पार्टी को इस नजरिए से सोचना होगा। महाराष्ट्र के नतीजों से दिल्ली में कुछ महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी उत्साह में होगी। कांग्रेस जहां उसके साथ जाने का दबाव बना सकती है, वहीं आम आदमी पार्टी कुछ और मुफ्तिया वादों के साथ मैदान में मजबूती से उतर सकती है।

महाराष्ट्र के चुनावों में असली उत्तराधिकारी कौन का सवाल भी हावी था। शिवसेना को दोनों धड़े हों या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों खेमे, सभी खुद को ही असली शिवसेना और असली एनसीपी बता रहे थे। इस चुनाव में बेशक अजित पवार के खेमे की सीटें कम हुई हैं, लेकिन शरद पवार की एनसीपी से उसके ज्यादा ही विधायक जीते हैं। इसी तरह एकनाथ शिंदे की शिवसेना की सीटें बढ़ी हैं, जबकि हिंदुत्ववादी की बजाय सेकुलर चोला धारण करने वाले उद्धव ठाकरे की शिवसेना पिछड़ गई है। अब इन नतीजों के आधार पर अजित पवार की पार्टी असली एनसीपी होने का दावा करेगी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना भी खुद को असली और बाला साहब ठाकरे की असल उत्तराधिकारी बताएगी। ऐसे में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टियों के वजूद को बचाए रखने का संघर्ष होगा। सत्तावादी राजनीति में विधायक लंबे समय तक सत्ता से दूर नहीं रह सकते। आने वाले दिनों में शरद पवार और उद्धव ठाकरे का विधायक दल टूटे तो हैरत नहीं होनी चाहिए।

शरद पवार का कहना है कि कटेंगे तो बंटेंगे का असर भी महाराष्ट्र के चुनावों में दिखा। बीजेपी की अगुआई वाले गठबंधन के खिलाफ राज्य का 11 फीसद मुस्लिम वोट बैंक एकजुट हुआ। इसकी वजह से हिंदू वोट बैंक महायुति की ओर गोलबंद हुआ। वैसे जानकारों का मानना है कि मराठा आरक्षण की मांग रखने वाले मनोज जरांगे का पहले चुनाव लड़ने का ऐलान करना और बाद में शरद पवार आदि के दबाव में चुनाव से पैर पीछे खींचना भी महायुति की सफलता की वजह बना। इससे मनोज जरांगे की साख कमजोर हुई और मराठा वोटर महायुति की ओर लौट आया, जो लोकसभा चुनाव के दौरान उससे दूर हो गया था।

महाराष्ट्र के नतीजों से महायुति की अंदरूनी राजनीति पर भी असर पड़ने की संभावना है। भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को बिहार की राह पर ले चलना नहीं चाहेगी। ऐसे संकेत उसने दिए भी हैं। यानी वह देवेंद्र फणनवीस को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे आसानी से मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। इस मसले पर महायुति में तनाव दिख सकता है। जिसे खत्म करने के लिए बीजेपी आलाकमान को ऊर्जा लगानी पड़ेगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मसले पर राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठता है।

झारखंड के नतीजों ने एक रिकॉर्ड बनाया है। राज्य के गठन के बाद कोई भी सरकार दोबारा सत्ता में नहीं आ पाई है। हेमंत सोरेन यह रिकॉर्ड बनाने में कामयाब रहे हैं। इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा। इन नतीजों ने साबित किया है कि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को झारखंड की जनता ने स्वीकार नहीं किया। झारखंड की कमान बीजेपी की ओर से हिमंत विश्वशर्मा और शिवराज सिंह चौहान को दी गई थी। उत्तर पूर्व से बाहर हिमंत को पार्टी की ओर से पहला असाइनमेंट मिला था। इसमें अगर वे सफल होते तो उनकी राष्ट्रव्यापी छवि बनती। लेकिन वे इसमें नाकाम रहे हैं। अगर बीजेपी को झारखंड में कामयाबी मिलती तो शिवराज का भी कद बढ़ता। लेकिन फिलहाल इसमें ब्रेक लगता दिख रहा है। बीजेपी को चंपई सोरेन के जरिए कोल्हान में चमत्कार की उम्मीद थी, लेकिन चंपई कोई कमाल नहीं दिखा पाए। इसका असर उनके राजनीतिक कद पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने आदिवासी समुदाय की शख्सियत को राष्ट्रपति पद तक पहुंचाया, इसके बावजूद लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उसे आदिवासी सीटों पर समर्थन ना मिलना चिंता का विषय होगा। बीजेपी को अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा और आदिवासी वोटरों के बीच भरोसा कायम करने के लिए सोचना पड़ेगा।

पुराण दिग्दर्शन .... तीसरा अध्याय

वेदपुराण-परम्पराध्यायः

गतांक से आगे...

(23) उक्त ब्राह्मणग्रन्थ स्वयं पुराणों को अपने से अलग बता रहे हैं यथा: ननमेऽहनि किंचित् पुराणमाचक्षीत। (शतपथ 13 ।4 ।3 ।12) अर्थात् - यज्ञ के नवें दिन कुछ पुराण पढ़ा जाए।

यदि ब्राह्मणग्रन्थ ही पुराण होते तो वे अपने पाठ का ही आदेश न करते। कहाँ तक लिखें, ब्राह्मण भाग को मन्त्रभाग की भांति अविशेष वेद सिद्ध करने वाले सहस्रों प्रमाण संगृहीत किये जा सकते हैं। किसी भी ऋषि मुनि आचार्य के ग्रन्थ को उठाइये, सर्वत्र ब्राह्मणग्रन्थों की वैदिकता का उल्लेख मिलेगा । प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार आद्य शङ्कराचार्य, श्रीनिम्बार्काचार्य और श्री माध्वाचार्य आदि सभी विद्वानों ने एक स्वर से ब्राह्मणों का वेदत्व स्वीकार किया है।

इतने पर भी स्वामी दयानन्द और उनके अनुयायी अपनी बेसुरी तान का आलाप नहीं छोड़ते इसे सिवा दुराग्रह के और क्या कहा जा सकता है ?

ब्राह्मण भाम के वेदत्व में युक्तियें

यहां तक हमने प्रमाणों द्वारा ब्राह्मणभाग का वेद होना सिद्ध किया है। अब कतिपय युक्तियों द्वारा भी इसकी पुष्टि की जाती है जिससे युक्तिप्रमाणाभ्यां हि वस्तुसिद्धिः के अनुसार प्रतिवादियों को कुछ कह सकने का अवसर ही न मिल सके ।

(1) किसी भी ब्राह्मणग्रन्थ के आदि में अथवा अन्त में अथ शतपथपुराणंस् इति गोपथपुराणम् ऐसी पुष्पिका का उल्लेख नहीं अतः वे पुराण नहीं हो सकते।

(2) पुराण का सर्वविदित लक्षण - सर्ग प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंशानुचरित है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थ में उक्त विषयों का कहीं भी क्रमबद्ध वर्णन नहीं मिलता है। खास कर चन्द्र-सूर्य-वंशी और तत्तद् वंशीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों के चरित्र का तो कहीं भी उल्लेख नहीं।

क्रमशः ...

संविधान दिवस

डॉ. अजय खेमरिया

आज ही के दिन यानि (26 नवम्बर 1949) को हम भारतीयों का संविधान बनकर तैयार हुआ था। 75 वर्ष बाद हमारा संविधान क्या अपनी उस मौलिक प्रतिबद्धता की ओर उन्मुख हो रहा है जिसे इसके रचनाकारों ने अपनी भारतीयता के प्रधानतत्व को आगे रखकर बनाया था। आज इस सवाल को सेक्युलरिज्म के आलोक में विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि मूल संविधान की इबारत में यह अवधारणा कहीं थी ही नहीं इसे तो 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया है।

यहां सवाल यह भी उठाया ही जाना चाहिये कि जिस दलित चेतना के नाम पर अक्सर संविधान को बाबा साहब अंबेडकर की अस्मिता के साथ जोड़ा जाता है क्या उसके साथ बुनियादी खिलवाड़ 1976 में

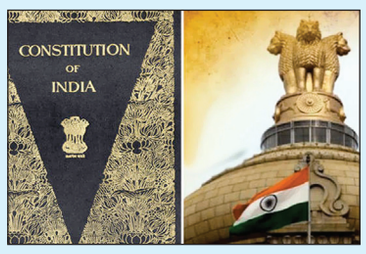

ही नहीं हो गया है। दलित वर्ग को यह भय अक्सर दिखाया जाता रहा है कि कतिपय मनुवादी मानसिकता आरक्षण को खत्म कर बाबा साहब के बनाये संविधान को बदलना चाहती है लेकिन कभी इस प्रश्न को नहीं उठाया जाता कि मूल संविधान के साथ बुनियादी छेड़छाड़ क्यों और किस मानसिकता के साथ की गई है ? आज इस बात पर संवाद होना ही चाहिये कि क्या मौलिक रूप से भारत का संविधान उस हिन्दू जीवन दृष्टि से शासन और राजनीति को दूर रहने की हिदायत देता है ? अगर हम मूल संविधान की प्रति उठाकर पन्नों को पलटते हैं तो हमें उसके अंदर सुविख्यात चित्रकार नन्दलाल बोस की कूची से बनाये हुए कुल 22 चित्र नजर आते हैं।

26 नबम्बर 1949 को जिस संविधान सभा ने नए विलेख को आत्मार्पित और आत्मसात किया है असल में वह परम्परा और आधुनिक भारत के सुमेलन का उद्घोष मात्र था। लेकिन कालान्तर में यह धारणा मजबूत हुई कि आधुनिक भारत का आशय सिर्फ पश्चिमी नकल, परंपरागत भारत के विसर्जन के साथ हिन्दू जीवन शैली को अपमानित करने से ही है। इसी बुनियाद पर भारत के शासन तंत्र को बढ़ाने की कोशिशें की गईं जबकि यह भुला दिया गया कि जिस सनातनी संस्कार से परम्परागत भारत भरा है वही आधुनिक भारत को वैश्विक स्वीकार्यता दिला सकता है। दुनिया में शांति, सहअस्तित्व, पर्यावरण सरंक्षण, जैसे आज के ज्वलंत संकटों का समाधान आखिर किस सभ्यता और सेक्युलरिज्म के पास है? सिवाय हमारे उन आदर्शों के जिन्हें आधुनिक लोग पिछड़ेपन की निशानी मानते हैं।

हमें यह याद रखना चाहिये कि जब तक सनातन सभ्यता की व्याप्ति सशक्त नहीं होगी भारत दुनिया में अपनी वास्तविक हैसियत हासिल नहीं कर सकता है। दुर्भाग्य से इसी आधार को शिथिल करने में एक बहुत बड़ा वर्ग लगा हुआ है। हमारे पूर्वजों के पास अद्भुत दिव्यदर्शन था इसलिए उन्होंने भारत को धर्मनिरपेक्ष नहीं बनाया बल्कि धर्मचित्रों को आगे रखकर लोक कल्याण के निर्देश स्थापित किये। धर्म हमारी सनातन निधि में इस्लाम या ईसाइयत की तरह पूजा पद्धति नहीं कर्तव्य का विस्तार है।

बहनों को सरकारी नेग अब चुनाव जीतने का शर्तिया फॉर्मूला!

अजय बोकिल

महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ भाजपानीत महाआघाड़ी की प्रचंड जीत और विपक्षी कांग्रेसनीत महाविकास आघाड़ी की दारूण पराजय एवं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगुवाई में यूपीए की सत्ता में शानदार वापसी के मूल में कॉमन फैक्टर इन राज्यों में सत्तारूढ़ सरकारों द्वारा महिलाओं को सीधा आर्थिक लाभ देना है।

महाराष्ट्र में यह कमाल युति सरकार की 'लाडकी बहिण' योजना ने तो झारखंड में झामुमो गठबंधन सरकार की 'मइया सम्मान योजना' ने किया। उस पर योगी आदित्यनाथ के 'बटेंगे तो कटेंगे' नारे ने महाराष्ट्र में बहुसंख्यक वोटरों को महायुति और एनडीए के पक्ष में एकजुट होने को इस कदर प्रेरित किया कि महायुति के घटक अजित पवार की राकांपा द्वारा खड़े किए कुछ मुस्लिम उम्मीदवार भी इस लहर में तर गए।

इसी नारे की बिना पर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा के उपचुनाव में 7 पर भगवा फहरा गए। इस चुनाव ने अब महाराष्ट्र में असली व नकली शिवसेना तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस की बहस को बेमानी करार दे दिया है, भले ही इसको लेकर कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। महाराष्ट्र में पहली बार मतदाता ने ठाकरे परिवार के नेतृत्व चाहे उद्धव हो या राज ठाकरे, को लगभग नकार दिया है। सत्ता के लोभ में बालासाहब ठाकरे का हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस व शरद पवार की राकांपा के साथ जाने वाले शिवसेना (उद्धव गुट) के प्रमुख उद्धव ठाकरे और बरसों से महाराष्ट्र की राजनीति धुरी रहे शरद पवार के नेतृत्व की चमक को इस हार ने बहुत फीका कर दिया है।

समग्रता में महाराष्ट्र के चुनाव को समझें तो शरद पवार की चाणक्य नीति को इस चुनाव में केन्द्रीय गृह मंत्री और भाजपा के चाणक्य अमित शाह ने न केवल जबर्दस्त पटखनी दी है बल्कि विपरीत विचारधारा के उद्धव को राज्य का मुख्यमंत्री बनाकर जो घोड़ापछाड़ दांव पवार ने भाजपा के खिलाफ चला था, शाह ने उसका ब्याज समेत बदला ले लिया

है। नतीजा यह रहा कि जिस राकांपा को मतदान के दिन तक मआवि का सबसे दमदार घटक माना जा रहा था, वह आघाड़ी की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। शाह ने संघ की आलोचना के बाद भी अजित पवार को साथ रखा। लोकसभा चुनाव में चाचा से मात खाने के बाद भतीजे अजित पवार ने इस बार जमकर ताकत झोंकी और चाचा को साफ संदेश दे दिया कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर महाराष्ट्र में इस चुनाव में भाजपा को अब तक की सर्वाधिक सीटें मिली हैं तो इसका श्रेय उप मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की मेहनत, पार्टी अनुशासन का पालन और धैर्य को भी जाता है।

यूं तो महाराष्ट्र और झारखंड दोनो राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर पूरे देश की नजर थी। लेकिन महाराष्ट्र के नतीजे देश की भावी राजनीति तय करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद देश में मोदी मैजिक फीका पड़ने और हिंदुत्व की धार भोंथरी होने की बात कही जा रही थी, वह जादू अब नए जलवे के साथ लौट रहा है।

यह हमने हरियाणा के विस चुनाव में देखा और अब महाराष्ट्र व यूपी में देख रहे हैं। हालांकि झारखंड में यह जादू नहीं चला तो इसकी वजह बीजेपी की गलत रणनीति और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से आदिवासियों में उनके प्रति उपजी सहानुभूति ज्यादा थी। लेकिन महाराष्ट्र में पार्टी की प्रचंड जीत ने झारखंड की हार के गम को काफी हद तक धो दिया है।

यह बात अब कांच की तरह साफ है कि महिलाओं को आर्थिक मदद देकर मतदाता के रूप में उनका समर्थन जीतने का जो लाजवाब गेमचेंजर नुस्खा मप्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने ईजाद किया था, वह न सिर्फ भाजपा बल्कि हर सत्तारूढ़ पार्टी के लिए जीत का शर्तिया नुस्खा साबित हो रहा है। यही कारण है कि महिलाएं बड़ी संख्या में वोट कर रही हैं और उस सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में वोट कर रही हैं, जो हर माह उनके खाते में निश्चित राशि सीधे जमा कर रही है। सभी मुख्यमंत्री इस आर्थिक मदद को राज्य की बहनों को 'भाई का नेग' करार दे रहे हैं। बदले में बहनाएं उन पर वोट न्यौछावर कर रही हैं। हरियाणा में हमने यह सैनी सरकार की 'लाडो बहना योजना' के रूप में तो महाराष्ट्र में लाडकी बहिण और झारखंड में 'मइया सम्मान योजना' के रूप में देखा। अब बाकी राज्यो में भी सरकारें अपनी सत्ताएं बचाने इसी राह बढ़ेंगी। संक्षेप में कहें तो अब महिलाएं ही सत्ता की रक्षक के रूप में उभर रही हैं। आश्चर्य नहीं कि केन्द्र में मोदी सरकार भी अगले आम चुनाव के पहले बहनों के लिए ऐसी ही कोई योजना लेकर आ जाए। इसमें खास बात यह है कि महिलाओं लाभार्थी बनाने के वादे विपक्षी पार्टियां भी अपने घोषणा पत्रों में उसी शिद्दत के साथ कर रही हैं, लेकिन बहनो को वादों से ज्यादा शायद देवाल भाई पर भरोसा है।

महाराष्ट्र चुनाव नतीजों में योगी आदित्यनाथ के चर्चित नारे 'बंटेंगे तो कटेंगे' का भी गहरा असर दिखा है। अधिकांश सीटों पर हिंदू वोट महायुति के पक्ष में एकजुट हुए हैं। यह एकजुटता भी प्रति-एकजुटता के रूप में ज्यादा है। क्योंकि 'बंटेंगे तो कटेंगे' में यह कहीं भी नहीं कहा गया कि एकजुटता का यह आह्वान निश्चित रूप से किसके खिलाफ है। लेकिन मुसलमानों ने इसे अपने खिलाफ माना और वे मोदी, योगी व भाजपा के विरूद्ध एकजुट हुए। हिंदू समाज में इसका प्रति ध्रुवीकरण स्वयमेव भाजपा व महायुति के पक्ष में हुआ। इस पूरे ध्रुवीकरण में कांग्रेस असहाय सी दिखी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी हाथ में संविधान की प्रति लहराते संविधान बचाने की गुहार लगाते दिखे। लेकिन 'संविधान बचाने' का मुद्दा उस 'काठ की हांडी' की तरह साबित हुआ, जो विस चुनाव के चूल्हे पर नहीं चढ़ सकी। योगी के बाद पीएम मोदी ने 'एक हैं तो सेफ हैं' का नारा दिया, उसका भी असर हुआ। मतदाताओ ने अपनी रोजमर्रा की तकलीफों, किसानों ने उपज का कम भाव मिलने की नाराजी, युवाओं ने बेरोजगारी जैसे जमीनी मुद्दों को दरकिनार कर महायुति को वोट किया।

महाराष्ट्र का यह पहला विस चुनाव है, जिसमें कोई भी पार्टी सदन में अधिकृत विपक्ष का दर्जा नहीं पा सकेगी। लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस रणनीतिक असमंजस और कमजोर संगठन के कारण अपने न्यूनतम आंकड़े पर जा पहुंची है। इन नतीजों के बाद शरद पवार, उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस को भी अपने वजूद को टिकाए रखने की लड़ाई नए सिरे से लड़नी पड़ेगी। उधर यूपी में भी बाबा योगी आदित्यनाथ ने 9 में से 7 विधानसभा सीटें जीतकर 2027 के विस चुनाव का सत्ताधीश कौन होगा, इसकी इबारत लिख दी है।

आज का इतिहास

1842 नोट्रे डेम विश्वविद्यालय स्थापना की गयी।
1851 लंदन-पेरिस के बीच टेलीग्राफ कनेक्शन शुरू किया गया।
1867 डेट्रॉइट के जेबी सदरलैंड द्वारा प्रथम अनुकूलित वातावरण रेल कार पेटेंट कराई गई।
1885 पहली बार उल्कापिंड की तस्वीर ली गयी।
1894 जर्मनी के गणितज्ञ और भौतिकशास्त्री हेनरी रोडल्फ हर्टज़ का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ।
1917 एडी लिविंगस्टोन के साथ विवादों को सुलझाने में असमर्थ, टोरेंटो ब्लूशर्ट्स के मालिक, कनाडा के नेशनल हॉकी एसोसिएशन के अन्य आइस हॉकी क्लब आधिकारिक तौर पर उस स्पोर्ट्स लीग को छोड़ने के लिए सहमत हुए और एक नई वन-नेशनल हॉकी लीग का आयोजन किया।
1922 हावर्ड कार्टर और लॉर्ड कार्नरवोन 3,000 से अधिक वर्षों में फिरौन तूतनखामुन के मकबरे के पहले लोग बने।
1939 सोवियत रेड आर्मी ने मेनिला पर हमला किया और फिर दावा किया कि आग फिनलैंड से उत्पन्न हुई, जिससे उन्हें कुछ दिनों बाद शीतकालीन युद्ध शुरू करने के लिए कैसियस बेली मिली।
1942 हम्फ्रे बोगार्टैंड इंग्रिड बर्गमैन द्वारा अभिनीत फिल्म कैसाब्लांका (पोस्टर चित्र) का प्रीमियर न्यूयॉर्क सिटीटो में हॉलीवुड थिएटर में किया गया, जो उत्तरी अफ्रीका के मित्र देशों के आक्रमण और कैस्केनका के कब्जे में है।
1948 विश्व का पहला पोलराइड कैमरा बॉस्टन, अमेरिका में बेचा गया।
1950 चीनी सेना ने कोरिया में यू.एन. लाइनों के पीछे 16 मील की दूरी पर हमला किया।
1950 कोरियाई युद्ध-चोसिन जलाशय और -चोंगचोन नदी की लड़ाइयों के साथ, चीन ने यूनाइटेड नेशन फोर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर पलटवार किया।
1966 फ्रांस की रेंस नदी के मुहाने पर विश्व के पहले ज्वारीय ऊर्जा संयत्र ने काम करना शुरू किया।
1967 लिस्बन में बादल फटने से करीब 450 लोग मरे।
1976 वार्सो संधि संगठन संयुक्त सचिवालय की स्थापना की गयी।
1977 एक वक्ता ने दक्षिण पूर्वी इंग्लैंड में प्रसारित इंटरगैलेक्टिक एसोसिएशन अनुरूपित सदर्न टेलीविज़न का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए दर्शकों को चेतावनी दी कि बुराई के अपने सभी हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए।
1983 लंदनहोर्ट्रो हवाई अड्डे पर ब्रिंकस-एमएटी के गोदाम में छह लुटेरों ने सेंध लगाई और तीन टन सोने के बुलियन चुराए।
1983 हथियारबंद डकैतों ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर ढाई करोड़ पाउंड के सोने की लूट की थी।

आखिर क्यों दुनिया में सबसे खास है भारत का संविधान

जयसिंह रावत

विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की शासन व्यवस्था को चलाने वाला संविधान अपने आकार और प्रकार में भी सबसे खास और विशाल है। यह लचीला भी है तो कठोर भी है। लचीलेपन का उदाहरण 1950 से लेकर अब तक इसमें 106 संशोधन होना है। जबकि इसकी कठोरता का उदाहरण यह कि इसमें समय के साथ संशोधन तो किए जा सकते हैं मगर इसकी सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणतंत्र की मूल भावना नहीं बदली जा सकती।

अब तक की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 1973 में केशवानन्द भारती बनाम केरल सरकार के फैसले में स्पष्ट कर चुकी है कि भारत की संसद को संविधान संशोधन के व्यापक अधिकार तो हैं मगर असीमित नहीं हैं और वह भी संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकती। मतलब यह कि संसद सर्वोच्च कानून निर्मात्री होने के बावजूद संविधान के तहत ही है।

हमारे संविधान में विविधता और धर्मनिरपेक्षता का सम्मान किया गया है। मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत और सामाजिक न्याय के प्रावधान इसे अद्वितीय बनाते हैं। यह विभिन्न संविधानों से प्रेरणा लेकर भारत की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला गया है। अपनी संशोधन क्षमता और सार्वभौमिक मताधिकार की दृष्टि से यह लोकतंत्र की मिसाल है

भारतीय संविधान को अपनी व्यापकता, समावेशिता और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के कारण विश्व में विशेष और अनोखा माना जाता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद थे (अब 470 से अधिक), जिन्हें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया। यह शासन, नागरिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत, संघीय ढांचे और प्रक्रियाओं को विस्तार से परिभाषित करता है, जिससे इसकी स्पष्टता और व्यापकता सुनिश्चित होती है।

हमारा संविधान जितना कठोर उतना ही लचीला भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को परिभाषित करता है। यह अनुच्छेद संसद को संविधान के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार देता है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इसका उद्देश्य संविधान को समय और परिस्थितियों के अनुसार लचीला और प्रासंगिक बनाए रखना है।

पिछले 74 सालों में इसमें 106 संशोधन हो चुके हैं। जो समय के साथ बदले परिवेश में शासन की आवश्यकतानुसार ढल सकता है। लचीलापन इसे समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूल बनाता है। इसमें कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से भी बदले जा सकते हैं तो कुछ काफी कठिन प्रक्रिया से गुजरते हैं। यह कठोरता इसे स्थिर और मजबूत बनाती है।

संविधान में संघीय ढांचे में राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन बनाए रखा गया है। संविधान ने मौलिक अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए अदालती समीक्षा की व्यवस्था दी है। इसमें आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र को अधिक शक्ति दी गई है। यह कठोरता और लचीलापन लोकतंत्र की रक्षा करता है। इस दृष्टिकोण से संविधान भारत की विविधता और बदलते समाज के लिए आदर्श बनता है।

हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत की शासन व्यवस्था को विश्व में सर्वोत्तम बनाने के लिये विश्व की प्रमुख शासन व्यवस्थाओं को संचालित करने वाले बेहतर संविधानों के अच्छे-अच्छे गुण निकाल कर इसमें समाहित किये हैं। जैसे संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय ढांचा कनाडा से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की सोच अमेरिका के बिल

ऑफ राइट्स से तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। इन प्रभावों के बावजूद, इसे भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के अनुसार ढाला गया।

भारत विश्व का सबसे विविधतापूर्ण देश है, जिसमें भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक विविधता को समेटा गया है। भारतीय संविधान ने इस विविधता को संरक्षित करने और हर नागरिक को समानता का अधिकार देने के लिए कई प्रावधान किए हैं। संविधान के अनुसार, भारत में 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। विभिन्न राज्यों को उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। यह संघीय ढांचा सुनिश्चित करता है कि राज्यों को अपनी विशिष्टता का सम्मान करने की स्वतंत्रता मिले।संविधान ने भारत को एक ''धर्मनिरपेक्ष'' राज्य घोषित किया है।

संविधान में हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है (अनुच्छेद 25-28)। धर्म के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है, और यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता हो।अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 29 और 30 का प्रावधान किया गया है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) दिया गया है। जाति, धर्म, लिंग, भाषा या जन्मस्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव की सख्त मनाही है। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि राज्य और धर्म अलग-अलग रहें।

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार नागरिकों के स्वतंत्रता, समानता और गरिमा की गारंटी प्रदान करते हैं। ये अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक विस्तृत हैं और लोकतंत्र का मूल आधार हैं। इनमें समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) जाति, धर्म, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को समाप्त करता है। स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) नागरिकों को अभिव्यक्ति, आंदोलन, पेशा चुनने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देता है। शोषण के खिलाफ अधिकार (अनुच्छेद 23-24) बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) सभी को अपने धर्म का पालन और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। संस्कृति और शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 29-30) अल्पसंख्यकों को अपनी सांस्कृतिक पहचान और शैक्षिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार देते हैं। साथ ही संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32) नागरिकों को उनके अधिकारों के हनन पर न्यायालय से सीधे अपील करने की अनुमति देता है।

राज्य के नीति निदेशक तत्व संविधान के भाग-4 (अनुच्छेद 36-51) में दिए गए हैं। ये तत्व राज्य को नीति निर्धारण और शासन संचालन में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। हालांकि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन ये देश को सामाजिक और आर्थिक न्याय, समानता, और कल्याणकारी राज्य की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण, श्रमिकों के अधिकार, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, और आर्थिक समानता जैसे प्रावधान शामिल हैं। इनके अंतर्गत गांधीवादी विचारधारा (स्वराज, ग्राम विकास) और सामाजिक-आर्थिक प्रावधान (मजदूरों की सुरक्षा, समान वेतन) दोनों को शामिल किया गया है। ये तत्व सरकार को यह निर्देश देते हैं कि वे ऐसी नीतियां बनाएँ जो गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दें, ताकि भारत एक समतावादी और कल्याणकारी राष्ट्र बने।

संविधान भारत का संघीय ढांचा मजबूत केंद्र के साथ राज्यों को स्वायत्तता प्रदान करता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह संघीय प्रणाली इकाईवादी बन जाती है, जो शासन में लचीलापन दिखाती है। हमारा संविधान न्यायपालिका को कानूनों की समीक्षा और उन्हें संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप बनाए रखने का अधिकार देता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता लोकतंत्र और कानून के शासन को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह एक जीवंत दस्तावेज है। यह आवश्यकता पड़ने पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार संसद को देता है। अनुच्छेद 32 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का ''हृदय और आत्मा'' कहा। यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है।

हार के बाद कांग्रेस नेताओं का वही पुराना राग- कब करेंगे विस्तार से सही विश्लेषण?

संतोष पाठक

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद एक बार फिर से कांग्रेस नेताओं का वही पुराना राग शुरू हो गया है। कांग्रेस के नेता इस करारी हार या यूं कहें कि महाराष्ट्र के इतिहास में मिली सबसे शर्मनाक पराजय का ठीकरा भी ईवीएम पर ही फोड़ने में जुट गए हैं। क्या वाकई ऐसा ही हुआ है? क्या वाकई ईवीएम के सहारे इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं? या फिर कांग्रेस नेताओं ने चुनावी हार का ऐसा मजबूत बहाना ढूंढ लिया है जो हर चुनावी हार के बाद वो दोहरा देते हैं ताकि पार्टी आलाकमान, उनसे सवाल न पूछे। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो यह पैदा हो गई है कि अपने जीवन में

एक भी चुनाव नहीं लड़ने वाले या फिर नहीं जीतने वाले नेताओं के साथ-साथ ऐसे नेता भी जनादेश पर और ईवीएम पर सवाल उठाने में जुटे हुए हैं, जो कई चुनाव जीत चुके हैं और जनादेश के बल पर ही लंबे समय तक सत्ता में रहे हैं। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, राज्यसभा के वर्तमान सांसद एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का 25 नवम्बर सोमवार को किया गया यह ट्वीट पढ़िए। दिग्विजय सिंह लिखते हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में वही हुआ जो भाजपा चाहती थी। उन्होंने 148 उम्मीदवार खड़े किए जिनमें से 132 जीत गये। स्ट्राइक रेट 89 प्रतिशत। वे यदि चाहेंगे तो शिवसेना (शिंदे) और एनसीपी (अजित पवार) के बिना भी सरकार बना सकते हैं। यह चुनाव भाजपा ने पूरा ईवीएम के माध्यम से टारगेटेड पोलिंग बूथ्स पर मैनीपुलेट कर जीत हासिल की है। लोग कहेंगे फिर झारखंड वे कैसे हार गये? आप ही सोचिए नरेंद्र मोदी, अमित शाह के लिए क्या झारखंड से महाराष्ट्र अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? इंडिया गठबंधन को चुनाव आयोग के व्यवहार पर और ईवीएम द्वारा चुनाव कराये जाने के विषय पर तत्काल चर्चा करना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया से जुड़ा हुआ कोई भी समझदार नेता या कार्यकर्ता, इतना सक्षम होता है कि वह अपने-अपने बूथ पर होने वाली वोटिंग का सटीक नतीजा बता सकता है। इसलिए यह कहना कि कांग्रेस नेताओं को सच का अहसास नहीं होगा, अपने आप में पूरी तरह से गलत होगा। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो यह है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस नेता जो तर्क देते हैं। उसे राहुल गांधी भी स्वीकार कर लेते हैं या उन्हें करना पड़ता है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भी राहुल गांधी ने अप्रत्याशित नतीजों का विश्लेषण करने की बात कही थी और राहुल गांधी के उसी ट्वीट को उनकी सोशल मीडिया टीम ने थोड़ा हेर-फेर कर महाराष्ट्र चुनाव में मिली हार के बाद भी चिपका दिया। यानी या तो राहुल गांधी हार के विश्लेषण को लेकर गंभीर नहीं है या फिर वरिष्ठ नेताओं की टोली उनपर इस कदर हावी हो गई है कि राहुल गांधी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। दोनों ही सूरतों में यह कांग्रेस, विपक्ष और लोकतंत्र तीनों के लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती है।

उद्धव और शरद पवार के लिए राजनीति में वापस लौटना कठिन

राज कुमार सिंह

हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भी प्रचंड जीत से भाजपा का वह आत्मविश्वास लौट आएगा, जो लोकसभा चुनाव में अकेले दम बहुमत से वंचित रहने पर डगमगाता लग रहा था। दूसरी ओर हाथ आती सत्ता हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में भी फिसल जाने के सदमे से उबर पाना विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के लिए आसान नहीं होगा। इन चुनाव परिणामों का मनोवैज्ञानिक असर अगले साल होने वाले दिल्ली और बिहार के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ेगा। बिहार में हुए चारों विधानसभा उप-चुनावों में राजग की जीत 'इंडिया' के लिए खतरे का ही संकेत है। पंजाब में 4 में से 3 विधानसभा उप-चुनाव जीत लेने को दिल्ली का सैमीफाइनल बता रहे 'आप' संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि दिल्ली में सत्ता की जंग इस बार पिछली बार जितनी आसान नहीं होगी। लोकसभा चुनाव परिणाम में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति पर विपक्षी गठबंधन महा विकास अघाड़ी भारी पड़ता नजर आया था। लोकसभा चुनाव में लगभग एक-तिहाई सीटों पर सिमट जाने के बावजूद महायुति के लिए संतोष की बात थी कि विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त के मामले में फासला ज्यादा नहीं था। मत प्रतिशत में भी ज्यादा अंतर नहीं था। इसीलिए महायुति ने हिम्मत हारे बिना जमीनी, राजनीतिक और चुनावी प्रबंधन की बिसात बिछाई और हारी हुई लग रही बाजी इस तरह पलट दी कि चुनौती देने वाले चेहरे उद्धव ठाकरे

को भी कहना पड़ा कि यह तो सुनामी है। अक्सर हार के बाद ई.वी.एम. समेत चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठाने वाले विपक्ष ने फिलहाल तो समीक्षा और आत्मविश्लेषण की बात ही कही है। दरअसल यह विपक्ष के लिए समीक्षा से भी ज्यादा आत्मविश्लेषण की घड़ी है। आखिर कुछ तो कारण हैं कि विपक्ष जीती दिख रही बाजी भी हार जाता है और भाजपा या उसके नेतृत्व वाला गठबंधन हारी हुई दिख रही बाजी भी जीत जाता है। महाराष्ट्र तो हरियाणा से भी 2 कदम आगे निकल गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा की महायुति महाराष्ट्र में 48 में से 17 सीटों पर सिमट गई थी। भाजपा के हिस्से तो मात्र 9 सीटें ही आई थीं। जिस तरह इस बार हरियाणा के साथ ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए गए तथा लोकसभा चुनावों के बाद से लोक-लुभावन योजनाओं और घोषणाओं की झड़ी लगा दी गई, उससे भी संकेत यही गया कि भाजपा को सत्ता की जंग की मुश्किलों का अहसास है। विधानसभा चुनाव में भाजपा के बाद सबसे बेहतर सफलता अजित की राकांपा की ही रही है। पिछली बार उद्धव की शिवसेना से गठबंधन के बावजूद 74 सीटें ही जीत पाई भाजपा ने इस बार 132 सीटें जीत कर सबको चौंका दिया है तो देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 100 से ज्यादा सीटें लड़कर भी मात्र 15 सीटें ही जीत पाई। अजित पवार की पार्टी 53 सीटों पर चुनाव लड़कर 41 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि चाचा शरद पवार की पार्टी 82 सीटों पर चुनाव लड़कर मात्र 10 सीटें ही जीत पाई। यह साधारण प्रदर्शन नहीं है, क्योंकि 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में शरद पवार की राकांपा की सफलता दर सबसे बेहतर 80 प्रतिशत रही थी, जबकि अजित की राकांपा की सफलता दर सबसे कम 25 प्रतिशत थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। विधानसभा चुनाव में तो उसने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बहुत पीछे छोड़ दिया है। शिंदे 81 सीटों पर चुनाव लड़ कर 57 सीटें जीतने में सफल हो गए, जबकि उद्धव 97 सीटों पर चुनाव लड़कर 20 सीटें ही जीत पाए। जाहिर है, विभाजन के बाद से जारी असली-नकली शिवसेना और राकांपा विवाद में जनता जनार्दन ने भी अपना फैसला सुना दिया है। राजनीति में भविष्यवाणी करना जोखिम भरा काम है, पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए महाराष्ट्र की राजनीति की मुख्यधारा में वापस लौट पाना आसान नहीं होगा। बेशक ये चुनाव परिणाम किसी गठबंधन के सुमेल या बेमेल होने का प्रमाण नहीं माने जा सकते क्योंकि लोकसभा चुनाव में अघाड़ी को मतदाताओं का समर्थन मिला तो विधानसभा चुनाव में महायुति को मिला है। चुनावी मुद्दे कमोवेश समान होने के बावजूद झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन की जीत महाराष्ट्र के जनादेश के विश्लेषण को और भी मुश्किल बना देती है।

भाजपा की हरसंभव कवायद के बावजूद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा-कांग्रेस-राजद-वाम दल सरकार को लगातार दूसरी बार जनादेश राजनीतिक दलों और नेताओं की विश्वसनीयता पर भी विचार की जरूरत को रेखांकित करता है।

निश्चय ही महाराष्ट्र और झारखंड के जनादेश का सबसे सकारात्मक पक्ष यह है कि मतदाताओं ने स्थिर सरकार के लिए स्पष्ट जनादेश दिया है। लोक-लुभावन योजनाएं और घोषणाएं मतदाताओं को आकर्षित करने में निश्चय ही सफल रहती हैं, लेकिन जन आकांक्षाओं पर खरा न उतरने पर होने वाली जन प्रतिक्रिया भी बहुत तीव्र होती है।

महाराष्ट्र में संघ शक्ति की जीत

गंगाधर ढोबले

महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे इस बार ऐतिहासिक और अभूतपूर्व रहे। भाजपा की लहर नहीं, सुनामी चली। इन कल्पनातीत और अनपेक्षित नतीजों ने भाजपा के सहयोगी दलों- शिंदे सेना और अजित पवार की एनसीपी की नैया भी पार लगा दी। कांग्रेस के नेतृत्व में उद्धव सेना और शरद पवार की एनसीपी की महाविकास आघाड़ी चारों खाने चित हो गई। राज ठाकरे की एमएनएस, प्रकाश आंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी, बच्चू कडू की तीसरी आघाड़ी शून्य के साथ अस्तित्व के संकट में आ गईं।

भाजपा की चमत्कारिक जीत का अंदाजा उसके स्ट्राइक रेट से आ जाता है। उसने 148 सीटों पर चुनाव लड़ा और 132 पर जीत हासिल की। स्ट्राइक रेट रहा 89%। इतना स्ट्राइक रेट शायद ही किसी पार्टी ने अब तक पाया हो। शिंदे सेना के भी मजे रहे। वह 81 सीटों पर लड़ी और 57 पर विजय पाई। स्ट्राइक रेट रहा 70%। अजित पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट तो शिंदे सेना से भी अधिक 75% के करीब है। वह 55 सीटों पर लड़ीं और 41 जीतीं। उधर, विपक्ष में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 16% है, जिसने 101 सीटों पर लड़कर 16 ही जीतीं। उद्धव सेना ने 95 सीटें लड़कर 20 जीतीं और स्ट्राइक रेट रहा 21%। शरद पवार की एनसीपी का स्ट्राइक रेट सबसे कम 12% ही है। उसने 87 सीटों पर चुनाव लड़ा और हाथ लगीं केवल 10।

सबसे अधिक मार शरद पवार की एनसीपी को पड़ी, जिससे उबरने की निकट भविष्य में संभावना दिखाई नहीं देती। शरद पवार का इस तरह हाशिए पर आ जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक युग का पटाक्षेप लगता है। दूसरा निष्कर्ष यह भी है कि जनता की अदालत ने शिंदे सेना को असली शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी को सही एनसीपी माना। शिंदे और अजित पवार अपनी पार्टियों को तोड़ते समय जितने विधायक अपने साथ ले गए थे, उससे

कई अधिक विधायकों को उन्होंने जितवाया। इससे दोनों का दबदबा बना रहेगा।

कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष की महाविकास आघाड़ी बुरी तरह से पिट गई। उनमें से किसी भी पार्टी को नेता प्रतिपक्ष का पद तक नहीं मिलेगा। यह पद पाने के लिए नियमानुसार 10त्न से अधिक यानी कम से कम 29 विधायक होने चाहिए।

महायुति की छप्परफाड़ जीत के कुछ प्रमुख कारण हैं- लाड़की बहीण (लाड़ली बहना) योजना, हिंदुत्व के वोटों का ध्रुवीकरण, लोकसभा चुनावों जैसी तटस्थता छोड़कर संघ के स्वयंसेवकों का पूरी शक्ति के साथ मैदान में उतर जाना, महायुति के घटक दलों का परस्पर सामंजस्य और गजब का समन्वय, मराठों के मुकाबले ओबीसी को जोड़ने में संघ की सफलता के कारण आरक्षण के मुद्दे का निष्प्रभावी हो जाना। यहां तक कि आरक्षण के नेता मनोज जरांगे के करीबी राजेश टोपे तक मराठों के वोट न मिलने से हार गए। यही नहीं, आरक्षण आंदोलन में जरांगे के गुरु रहे शरद पवार की पार्टी को भी मराठों ने नकार दिया। विपक्षी आघाड़ी में आपसी लड़ाई अंत तक खत्म नहीं हुई। लाड़ली बहना योजना और मुंबई में धारावी झुग्गी का विकास अदाणी को सौंपने के विरोध का आघाड़ी को नुकसान हुआ लगता है। शुरुआत में लाड़ली बहना योजना का आघाड़ी विरोध करती रही और अंत में महायुति से भी अधिक राशि देने का चुनावी वादा कर दिया। इस बदलते रुख से महिलाओं का आघाड़ी ने विश्वास खो दिया। महिलाओं का मतदान पहली बार 6% से अधिक बढ़ा। 12 से अधिक क्षेत्रों में उन्होंने पुरुषों से अधिक मतदान किया। लाड़ली बहना में मुस्लिम महिलाएं भी बहुतायत से हैं, जो अपने परंपरागत वोटबैंक से छितरकर महायुति के साथ हो लीं।

मुस्लिम वोट बैंक ने भी इस बार विपक्षी आघाड़ी का साथ नहीं दिया। मुस्लिम वोटिंग अक्सर 80% के आसपास होती है, इस बार लगभग आधी रही। मुस्लिम महिलाओं को घटा दिया जाए तो यह प्रतिशत और कम हो जाएगा। वैसे भी सभी मुस्लिम कांग्रेस या उसके सहयोगी दलों के साथ नहीं जाते। खासकर पिंजारी आदि पसमांदा मुसलमानों में ज्यादतर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के वोटर हैं।

कांग्रेस लोकसभा चुनावों में जीत के कारण मुगालते में रही। अंत तक उसकी घटक दलों से खींचतान चलती रही। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अपने टूटे धड़े के लोगों को 'गद्दारज्गद्दार' कहते रहे और अदाणी को धारावी के विकास का काम देने का विरोध करते रहे। दोनों नैरेटिव को जनता ने नकार दिया। अजित पवार ने शरद पवार की अदाणी से मिलीभगत की ऐन मौके पर पोल खोलकर पांसा पलट दिया। लोकसभा चुनाव में 'संविधान और आरक्षण को खतरे में' बताकर आघाड़ी ने वोटरों को अपनी ओर मोड़ दिया था। इस बार यह काम नहीं आया। इसके विपरीत भाजपा के 'बटेंगे तो कटेंगे' और 'एक हैं तो सेफ है' के नारों ने हिंदू वोटों को जुटाने में अहम भूमिका निभाई। इसलिए इसे 'संघ शक्ति' और 'नारी शक्ति' की विजय भी कहा जा सकता है।

महाराष्ट्र में महायुति की असाधारण जीत

अनिल सिन्हा

महाराष्ट्र का यह चुनाव परिणाम असाधारण है। इसलिए इस चुनाव परिणाम का विश्लेषण भी विशेष तरीके से होना चाहिए। एक बात तो बहुत साफ दिखाई देती है कि भाजपा को राज्य भर में सफलता मिली है। इसका मतलब यह है कि वोटों के बंटवारे में कोई क्षेत्रीय फैक्टर नहीं था। अब तक यह माना जाता था कि विदर्भ कांग्रेस का गढ़ है और पश्चिम महाराष्ट्र एनसीपी का। यह भी माना जाता था कि कोंकण को छोड़ दें, तो भाजपा या उसके सहयोगी दलों- एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी का अपना कोई गढ़ नहीं है। लेकिन इस चुनाव परिणाम ने उन सारी धारणाओं पर पूर्णविराम लगा दिया है और भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति को किसी क्षेत्र-विशेष ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य को अपना गढ़ घोषित करने का हक दे दिया है।

इस चुनाव परिणाम के बाद महायुति को कोई यह चुनौती नहीं दे सकेगा कि महाराष्ट्र में उनका कोई व्यापक जनाधार नहीं है। हालांकि इस परिणाम के बाद यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र भी गुजरात के रास्ते पर चल पड़ा है, जहां विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है? महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन के सफाये को लेकर तमाम तरह की बहस हो रही है। मीडिया के एक हिस्से का कहना है कि 'लाडकी बहना' योजना ने महिलाओं तथा उनके परिवार के सदस्यों को लुभाने में अहम भूमिका निभायी। कुछ लोग इसे भाजपा के चुनाव-प्रबंधन का कमाल मान रहे हैं।

कुछ लोग यह बताने में मशगूल हैं कि 'एक हैं तो सेफ हैं' के नारे ने अपना चमत्कार दिखाया। कुछ लोग कह रहे हैं कि मराठा आंदोलन ने ओबीसी के एक बड़े तबके में असुरक्षा की भावना पैदा की और यह भावना ही उन्हें भाजपा की ओर ले आयी। हालांकि इस तर्क में ज्यादा दम दिखाई नहीं देता। वास्तविकता यह है कि महायुति के तीन शीर्ष नेताओं-देवेंद्र फडनवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार में कोई भी ओबीसी नहीं है। यही नहीं, महायुति की सरकार ने मराठों को ओबीसी कोटे में आरक्षण का रास्ता निकालने का आश्वासन दे रखा है, जिसे लेकर उस तबके में काफी चिंता है।

जाहिर है कि इस बड़ी पराजय के बाद भाजपा ने राहुल गांधी को निशाना बनाया है। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में कांग्रेस की उम्मीदें धरी की धरी रह गयीं। भाजपा संविधान की रक्षा करने के राहुल गांधी के दावे को चुनौती दे रही है, साथ ही, कह रही है कि लोगों ने गांधी परिवार को खारिज कर दिया है। हालांकि वायनाड लोकसभा क्षेत्र, झारखंड विधानसभा के चुनाव और देश के विभिन्न हिस्सों के उपचुनाव बतलाते हैं कि राहुल गांधी और उनके परिवार के प्रति लोगों में अविश्वास जैसी भावना नहीं है, जैसी कि बतायी जा रही है।

वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री को शरद पवार और उद्धव ठाकरे से चुनौती मिल रही थी। इस राज्य में उद्योगों को गुजरात स्थानांतरित करने का मुद्दा गरम था और इसकी वजह से लोग उनसे नाराज भी बताये जा रहे थे। पराजय के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे यह सवाल कर रहे हैं कि उनकी सभाओं में जो भीड़ आ रही थी, क्या वह पहले से यह तय कर चुकी थी कि उन्हें वोट नहीं देगी। अगर वह यह तय कर चुकी थी, तो फिर वह उनकी सभाओं में आखिर क्यों आ रही थी? बेशक उद्धव ठाकरे की चुनावी सभाएं प्रधानमंत्री की सभाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा उत्साह से भरी हुई थीं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तथा एनसीपी नेता शरद पवार की चुनावी सभाएं भी जोरदार रहीं। लेकिन यह तथ्य है कि जनता की वह गर्मजोशी वोट देने के मामले में नजर नहीं आई।

अलबत्ता यह भी सच है कि महायुति की चुनावी तैयारियों और रणनीतियों की तुलना में महाविकास आघाड़ी की तैयारी अधूरी थी। यही नहीं, सीटों और नेता के मामले में आपसी असहमति का भी उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इंडिया गठबंधन की पराजय इतनी बड़ी है कि विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी संशय है।

हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी से निभाया भगवान श्रीकृष्ण ने

भगवान श्रीकृष्ण ने हर रिश्ता बड़ी ही ईमानदारी से निभाया और हर रिश्तों को उन्होंने महत्व दिया। आओ जानते हैं कि इस संबंध में कुछ खास जानकारी।

मित्रता का रिश्ता

भगवान श्रीकृष्ण के हजारों सखा या कहें कि मित्र थे। श्रीकृष्ण के सखा सुदामा, श्रीदामा, मधुमंगल, सुबाहु, सुबल, भद्र, सुभद्र, मणिभद्र, भोज, तोककृष्ण, वरूथप, मधुकंड, विशाल, रसाल, मकरन्द, सदानन्द, चन्द्रहास, बकुल, शारद, बुद्धिप्रकाश, अर्जुन आदि थे। श्रीकृष्ण की सखियां भी हजारों थीं। राधा, ललिता आदि सहित कृष्ण की 8 सखियां थीं।

ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार सखियों के नाम इस तरह हैं- चन्द्रावली, श्यामा, शैव्या, पद्या, राधा, ललिता, विशाखा तथा भद्रा। कुछ जगह ये नाम इस प्रकार हैं- चित्रा, सुदेवी, ललिता, विशाखा, चम्पकलता, तुंगविद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी और सुदेवी। कुछ जगह पर ललिता, विशाखा, चम्पकलता, चित्रादेवी, तुंगविद्या, इन्दुलेखा, रंगदेवी और कृत्रिमा (मनेली)। इनमें से

गईं सभी महिलाएं कृष्ण की सखियां थीं। द्रौपदी भी श्रीकृष्ण की सखी थीं। श्रीकृष्ण ने सभी के साथ अंत तक मित्रता का संबंध निभाया।

प्रेमी कृष्ण

कृष्ण को चाहने वाली अनेक गोपियां और प्रेमिकाएं थीं। कृष्ण-भक्त कवियों ने अपने काव्य में गोपी-कृष्ण की रासलीला को प्रमुख स्थान दिया है। पुराणों में गोपी-कृष्ण के प्रेम संबंधों को आध्यात्मिक और अति श्रांगारिक रूप दिया गया है। महाभारत में यह आध्यात्मिक रूप नहीं मिलता, लेकिन पुराणों में मिलता है। उनकी प्रेमिका राधा, रुक्मिणी और ललिता की ज्यादा चर्चा होती है।

पति कृष्ण

भगवान श्रीकृष्ण की 8 पत्नियां थीं- रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, मित्रवंदा, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा और कालिंदी। इनसे श्रीकृष्ण को लगभग 80 पुत्र हुए थे।

भाई कृष्ण

कृष्ण की 3 बहनें थीं- एकानंगा (यह यशोदा की पुत्री थीं), सुभद्रा और द्रौपदी (मानस भगिनी)। कृष्ण के भाइयों में नेमिनाथ, बलराम और गद थे।

श्रीकृष्ण के माता पिता

श्रीकृष्ण के माता पिता वसुदेव और देवकी थे, परंतु उनके पालक माता पिता नंदबाबा और माता यशोदा थीं। श्रीकृष्ण ने इन्हीं के साथ अपनी सभी सौतेली माता रोहिणी आदि सभी के सात बराबरी का रिश्ता रखा।

अन्य रिश्तों में श्रीकृष्ण

श्रीकृष्ण ने अपनी बुवाओं से भी खूब रिश्ता निभाया था। कुंती और सुतासुभा से भी रिश्ता निभाया। कुंती को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करूंगा और सुतासुभा को वचन दिया था कि मैं तुम्हारे पुत्र शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करूंगा। इसी प्रकार सुभद्रा का विवाह कृष्ण ने अपनी बुआ

पुत्र साम्ब का विवाह दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से किया था। श्रीकृष्ण के रिश्तों की बात करें तो वे बहुत ही उलझे हुए थे। श्रीकृष्ण ने अपने भांजे अभिमन्यु को शिक्षा दी थी और उन्होंने ही उसके पुत्र की गर्भ में रक्षा की थी।

शत्रुता का रिश्ता

इसी तरह श्रीकृष्ण ने अपनी शत्रुता का रिश्ता भी अच्छे से निभाया था। उन्होंने कंस, जरासंध, शिशुपाल, भौमासुर, कालय यवन, पौंड्रक आदि सभी शत्रुओं को सुधरने के भरपूर मौका दिया और अंत में उनका वध कर दिया।

रक्षक कृष्ण

भगवान श्रीकृष्ण ने किशोरावस्था में ही चाणूर और मुष्टिक जैसे खतरनाक मल्लों का वध किया था, साथ ही उन्होंने इंद्र के प्रकोप के चलते जब वृंदावन आदि ब्रज क्षेत्र में जलप्रलय हो चली थी, तब गोवर्धन पर्वत अपनी अंगुली पर उठाकर सभी ग्रामवासियों की रक्षा की थी।

शिष्य कृष्ण

भगवान श्रीकृष्ण के गुरु सांदीपनी थे। उनका आश्रम अवंतिका (उज्जैन) में था। कहते हैं कि उन्होंने जैन धर्म में 22वें तीर्थंकर नेमीनाथजी से भी ज्ञान ग्रहण किया था। श्रीकृष्ण गुरु दीक्षा में सांदीपनी के मृत पुत्र को यमराज से मुक्ति कराकर ले आए थे।

चंद्र की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या कहते हैं पुराण? चंद्रमा की जन्म कथा

सुंदर सलोने चंद्रमा को देवताओं के समान ही पूजनीय माना गया है। चंद्रमा के जन्म की कहानी पुराणों में अलग-अलग मिलती है। ज्योतिष और वेदों में चंद्र को मन का कारक कहा गया है। वैदिक साहित्य में सोम का स्थान भी प्रमुख देवताओं में मिलता है। अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवों के समान ही सोम की स्तुति के मंत्रों की भी रचना ऋषियों द्वारा की गई है।

पुराणों के अनुसार चंद्र की उत्पत्ति

मत्स्य एवं अग्नि पुराण के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचने का विचार किया तो सबसे पहले अपने मानसिक संकल्प से मानस पुत्रों की रचना की। उनमें से एक मानस पुत्र ऋषि अत्रि का विवाह ऋषि कर्दम की कन्या अनुसुइया से हुआ जिससे दुर्वासा, दत्तात्रेय व सोम तीन पुत्र हुए। सोम चंद्र का ही एक नाम है। पद्म पुराण में चंद्र के जन्म का अन्य वृतांत दिया गया है। ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्र अत्रि को सृष्टि का विस्तार करने की आज्ञा दी। महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नाम का तप आरंभ किया। तप काल में एक दिन महर्षि के नेत्रों से जल की कुछ बूंदें टपक पड़ी जो बहुत प्रकाशमय थीं। दिशाओं ने स्त्री रूप में आकर पुत्र प्राप्ति की कामना से उन बूंदों को ग्रहण कर लिया जो उनके उदर में गर्भ रूप में स्थित हो गया। परंतु उस प्रकाशमान गर्भ को दिशाएं धारण न रख सकीं और त्याग दिया।

उस त्यागे हुए गर्भ को ब्रह्मा ने पुरुष रूप दिया जो चंद्रमा के नाम से प्रख्यात हुए। देवताओं, ऋषियों व गंधर्वों आदि ने उनकी स्तुति की। उनके ही तेज से पृथ्वी पर दिव्य औषधियां उत्पन्न हुई। ब्रह्मा जी ने चंद्र को नक्षत्र, वनस्पतियों, ब्राह्मण व तप का स्वामी नियुक्त किया।

स्कंद पुराण के अनुसार जब देवों तथा दैत्यों ने क्षीर सागर का मंथन किया था तो उस में से चौदह रत्न निकले थे। चंद्रमा उन्हीं चौदह रत्नों में से एक है जिसे लोक कल्याण हेतु, उसी मंथन से प्राप्त कालकूट विष को पी जाने वाले भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। पर ग्रह के रूप में चंद्र की उपस्थिति मंथन से पूर्व भी सिद्ध होती है। स्कंद पुराण के ही माहेश्वर खंड में गर्गाचार्य ने समुद्र मंथन का मुहूर्त निकालते हुए देवों को कहा कि इस समय सभी ग्रह अनुकूल हैं। चंद्रमा से गुरु का शुभ योग है। तुम्हारे कार्य की सिद्धि के लिए चंद्र बल उत्तम है। यह गोमंत मुहूर्त तुम्हें विजय देने वाला है। अतः यह संभव है कि चंद्रमा के विभिन्न अंशों का जन्म विभिन्न कालों में हुआ हो। चंद्र का विवाह दक्ष प्रजापति की नक्षत्र रूपी 27 कन्याओं से हुआ जिनसे अनेक प्रतिभाशाली पुत्र हुए। इन्हीं 27 नक्षत्रों के भोग से एक चंद्र मास पूर्ण होता है।

इस मंदिर में मूर्तियों से निकलती हैं आवाजें

पत्थर की होती है, लेकिन जिस भी देवी या देवता की यह मूर्ति बनाई गई है उन देवी या देवताओं के अस्तित्व और उनकी शक्ति को नहीं नकारा जा सकता। आए दिन देवी या देवता अपने होने का अहसास कराते रहते हैं। इसी अहसास को चमत्कार कहा जाता है। ऐसा ही एक चमत्कार बिहार के बक्सर में स्थित देवी के एक मंदिर में देखने को मिला। यहां आकर आपको दुर्गा शक्ति के होने पर यकीन हो जाएगा क्योंकि यहां की मूर्तियां आपसे बात करती है। जब वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की तो उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया। यह मंदिर 400 वर्ष पुराना है। प्रसिद्ध तांत्रिक भवानी मिश्र ने करीब 400 वर्ष पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। तब से आज तक इस मंदिर में उन्हीं के परिवार के सदस्य पुजारी बनते रहे हैं। तंत्र साधना से ही यहां माता की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। दरअसल, तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध बिहार के इस इकलौते राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर में यहां पर किसी के नहीं होने पर आवाजें सुनाई देती हैं। इस मंदिर में दस महाविद्याओं काली, त्रिपुर भैरवी, धुमावती, तारा, छिन्न मस्ता, षोडसी, मातंगड़ी, कमला, उग्र तारा, भुवनेश्वरी की मूर्तियां स्थापित हैं। इसके अलावा यहां

काल भैरव व मातंगी भैरव की प्रतिमा स्थापित की गई है। यहां साधना करने वाले हर साधकों की हर तरह की मनोकामना पूर्ण होती है। देर रात तक साधक इस मंदिर में साधना में लीन रहते हैं। मंदिर में प्रधान देवी राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है। तांत्रिकों की आस्था इस मंदिर के प्रति अटूट

तरह की आवाजें सुनाई देती हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर की सबसे अनोखी मान्यता यह है कि निस्तब्ध निशा में यहां स्थापित मूर्तियों से बोलने की आवाजें आती हैं। मध्य-रात्रि में जब लोग यहां से गुजरते हैं तो उन्हें आवाजें सुनाई पड़ती हैं। वैज्ञानिकों की मानें, तो यह कोई वहम नहीं है। इस

पर शब्द भ्रमण करते रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी मान लिया है कि हां पर कुछ न कुछ अजीब घटित होता है, जिससे कि यहां पर आवाज आती है। मानो या न मानो यह एक चमत्कार ही है कि यहां अजीब तरह के आवाजें आती है जो कि किसी मानव की आवाजों की तरह की है। माना जाता है कि संपूर्ण अखंड भारत में जहां भी माता के शक्तिपीठ हैं वे सभी जागृत और सिद्ध शक्तिपीठ हैं।

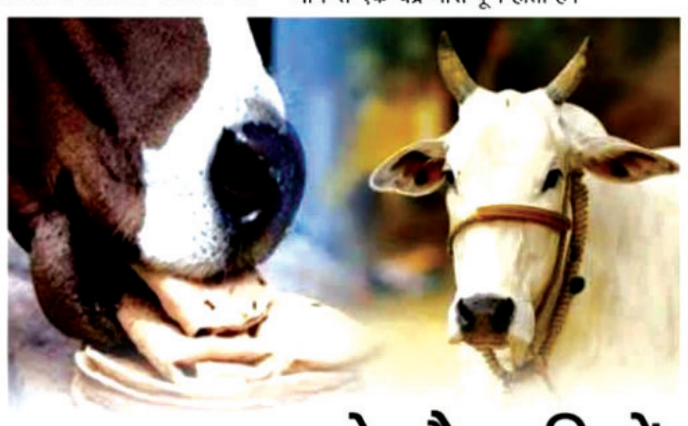

क्या गाय, कुत्ते और पक्षियों को पानी पिलाने से खुल जाते हैं किस्मत के दरवाजे

हिन्दू धर्म में कुछ पशु और पक्षियों को बहुत ही शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार इन्हें अन्न और जल देने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। प्रत्येक हिन्दू घर में जब भोजन बनता है तो पहली रोटी गाय के लिए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए होती है। भोजन करने के पूर्व अग्नि को उसका कुछ भाग अर्पित किया जाता है जिसे अग्निहोत्र कर्म कहते हैं। प्रत्येक हिन्दू को भोजन करते वक्त थाली में से 3 ग्रास (कोल) निकालकर अलग रखना होता है। यह तीन कोल ब्रह्मा, विष्णु और महेश के लिए या मन कथन के अनुसार गाय, कौए और कुत्ते के लिए भी रखा जा सकता है।

गाय - गाय को पत्ते पर भोजन परोसकर जल देने से भाग्य जागृत होता है। गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है, जो भाग्य को जागृत करने की क्षमता रखती है। गाय को अन्न और जल देने से सभी तरह के संकट दूर होकर घर में सुख, शांति और समृद्धि के द्वारा खुल जाते हैं। प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाने गुरु और शुक्र बलवान होता और धन-समृद्धि बढ़ती है।

कुत्ता - कुत्त को पत्ते पर भोजन परोसकर जल पिलाने से भैरव महाराज प्रसन्न होते हैं और हर तरह के आकस्मिक संकटों से वे भक्त की रक्षा करते हैं। कुत्ता आपकी राहु, केतु के बुरे प्रभाव और यमदूत, भूत प्रेत आदि से रक्षा करता है। कुत्ते को प्रतिदिन भोजन देने से जहां दुश्मनों का भय मिट जाता है वहीं व्यक्ति निडर हो जाता है। ज्योतिषी के अनुसार केतु का प्रतीक है कुत्ता। कुत्ता पालने या कुत्ते की सेवा करने से केतु का अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाता है। पितृ पक्ष में कुत्तों को मीठी रोटी खिलानी चाहिए।

कौवा- कौए के लिए छत या भूमि पर भोजन परोसकर सकोरे में उसके लिए जल रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौआ को यमदूत, पितर और देवपुत्र भी माना गया है। कौए को भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं कि यदि कौआ आपका भोजन ग्रहण कर ले तो समझो आपके पितर आपसे प्रसन्न और तृप्त हैं और यदि नहीं करें तो समझो कि आपके पितर आपसे नाराज और अतृप्त हैं।

चींटी - चींटियों के लिए पत्ते पर भोजन परोसा जाता। उनके बिल हों, वहां चूरा कर भोजन डाला जाता है। इससे सभी तरह के संकट मिट जाते हैं और घर परिवार में सुख एवं समृद्धि आती है।

देवता - देवबलि अर्थात पत्ते पर देवी देवतों और पितरों को भोजन परोसा जाता है। बाद में इसे उठाकर घर से बाहर उचित स्थान रख दिया जाता है।

पक्षी - पक्षियों को जल अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही हमारे जीवन के संकट मिट जाते हैं। नियमित जल पिलाने से भाग्य जागृत हो जाते हैं और किसी कार्य में आ रही रुकावट दूर होती है। हर कार्य आसानी से होने लगते हैं।

कुंडली की जांचे पन्ना पहनने के नुकसान भी है

पन्ना बुध ग्रह का रत्न है। बुध ग्रह वाणी, व्यापार, बहन, बुआ, मौसी आदि का कारक है। यह रत्न गहरे से हल्के हरे रंग का होता है। पन्ना मुख्यतः 5 रंगों में पाया जाता है। तोते के पंख के समान रंग वाला, पानी के रंग जैसा, सरेस के पुष्प के रंगों वाला, मयूरपंख जैसा और हलके संदुल पुष्प के समान होता है। पन्ना रत्न किसे पहनना चाहिए और किसे नहीं यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि कुंडली की जांच किए बगैर इसे पहनने के नुकसान भी है।

किसे पन्ना धारण करना चाहिए

- लग्न कन्या या मिथुन है तो पन्ना रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन यह भी देखना जरूरी है कि लग्न में कौनसा ग्रह है या लग्न के सामने सप्तम भाव में कौनसा ग्रह है।
- कुंडली को देखकर यदि किसी रोगी को पन्ना पहनाया जाता है तो उसके बल में वृद्धि होती है आरोग्य का सुख मिलता है।
- मिथुन लग्न वाले यदि पन्ना धारण करे तो पारिवारिक परेशानी कम होती है।
- कन्या लग्न यदि पन्ना धारण करे तो राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में लाभ पा सकते हैं।
- यदि बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो और बुध 8वें या 12वें भाव में नहीं हो तो पन्ना पहनने से लाभ मिलेगा।
- यदि बुध, मंगल, शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या उस पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पन्ना पहना जा सकता है। इससे नौकरी व्यवसाय में रुकावट दूर होगी।
- लाल किताब अनुसार यदि किसी घर में कोई ग्रह सोया हुआ हो तो उस घर को और उस ग्रह के प्रभाव को जाग्रत करने के लिए उस घर का रत्न धारण करें। जैसे यदि तीसरे में बुध नहीं है तो तीसरे के लिए बुध का रत्न धारण करें। इससे बुध के अच्छे प्रभाव मिलना प्रारंभ होंगे।
- यदि आपकी कुंडली में बुध मीन राशि का होकर बुरा प्रभाव दे रहा है तो पन्ना पहन सकते हैं।

पन्ना किसे धारण नहीं करना चाहिए

- लाल किताब के अनुसार बुध तीसरे या 12वें हो तो पन्ना नहीं पहनना चाहिए इससे नुकसान होगा।
- ज्योतिष के अनुसार 6, 8, 12 का बुध स्वामी हो तो पन्ना पहनने से अचानक नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले किसी ज्योतिष को कुंडली दिखाएं फिर ही पहनें।
- यदि बुध की महादशा चल रही है और बुध 8वें या 12वें भाव में बैठा है तो भी पन्ना धारण करने से समस्या उत्पन्न हो सकती है।
- नकली, अशुद्ध, टूटा-फूटा, धब्बेदार, चमकदार, स्वर्ण रंग का या अन्य रंग का पन्ना धारण करने से धन, समृद्धि और संतान पक्ष का नाश हो जाता है।
- उचित धातु, नक्षत्र, दिन और ग्रहों की स्थिति देखे बगैर पन्ना धारण किया है तो वह भी नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है।

पन्ना पहनने के फायदे

- पन्ना धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। इससे बुद्धि तेज होने लगती है।
- हाजमा अच्छा करने के लिए भी इसे धारण करते हैं।
- नौकरी और व्यापार में उन्नति के लिए भी इसे धारण करने की सलाह दी जाती है।
- पन्ना धारण करने से वाणी प्रभावशाली हो जाती है।
- पन्ना धारण करने से अधूरी तमन्नाएं पूरी होने लगती हैं।
- घर में पन्ना रत्न उचित स्थान पर रखने से अन्न-धन्न आदि में वृद्धि होती है, सुयोग्य संतान का सुख मिलता है।
- पन्ना पहनने से यदि बुद्ध उत्तम प्रभाव देने लगता है तो जातक की बहन की जिंदगी में भी परेशानियां कम हो जाती है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

अडानी मुद्दे पर हंगामे के बीच राज्यसभा स्थगित

नईदिल्ली। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक आरंभ होने पर सदन ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 13 नोटिस मिले हैं। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के नीरज डांगी, प्रमोद तिवारी और अखिलेश प्रसाद सिंह और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों पर संसद में चर्चा की मांग को लेकर नोटिस दिए थे। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सहित विपक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने मणिपुर हिंसा और उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के मुद्दे पर नोटिस दिए थे।

नाना पटोले ने महाराष्ट्र कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा दिया

मुंबई। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने हाल ही में संपन्न राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद सोमवार को इस्तीफा दे दिया। पटोले के इस्तीफे से कांग्रेस पार्टी को करारा झटका लगा है, जिसने 103 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें से उसे सिर्फ 16 सीटें ही मिल पाईं - राज्य में उसका अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन। पटोले खुद भंडारा जिले के सकोली निर्वाचन क्षेत्र में बमुश्किल अपनी सीट बचा पाए, जहां उन्हें सिर्फ 208 वोटों के मामूली अंतर से जीत मिली। महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भाजपा के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 232 सीटों पर जीत हासिल की, जो बहुमत के लिए जरूरी 50 सीटों की सीमा से कहीं ज्यादा है। इसके विपरीत, एमवीए, जिसमें कांग्रेस, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी शामिल हैं, ने अपनी सामूहिक ताकत को ढहते हुए देखा।

शरद पवार, प्रियंका चतुर्वेदी और राउत का क्या होगा?

मुंबई। अपनी पार्टियों में पर्याप्त समर्थन के अभाव में, एनसीपी (सपा) अध्यक्ष शरद पवार के साथ-साथ प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना (यूबीटी) के संजय राउत राज्यसभा में वापसी नहीं कर पाएंगे। 3 अप्रैल, 2020 को छह साल के कार्यकाल के लिए चुने गए, पवार और चतुर्वेदी 3 अप्रैल, 2026 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, जबकि 22 जुलाई, 2022 को चुने गए संजय राउत 22 जुलाई, 2028 तक अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) दोनों के सीमित समर्थन के साथ, उनके दोबारा चुनाव की संभावना कम है। पवार ने पहले कहा था कि राज्यसभा में यह उनका अंतिम कार्यकाल होगा। शरद पवार ने पहले कहा था कि राज्यसभा में यह उनका अंतिम कार्यकाल होगा। महायुति गठबंधन ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में 235 सीटें और 49.6 प्रतिशत वोट शेयर हासिल करके भारी जीत हासिल की।

संभल हिंसा पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा

नईदिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के संभल में हिंसा के लिए सोमवार को राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि इस मामले में उच्चतम न्यायालय को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि प्रशासन द्वारा सभी पक्षों को सुने बिना और संवेदनहीनता के साथ कार्रवाई की गई। राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''संभल में हालिया विवाद पर राज्य सरकार का पक्षपात और जल्दबाज़ी भरा रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंसा और गोलीबारी में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।'' उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन द्वारा सभी पक्षों को सुने बिना और संवेदनहीनता से की गई कार्रवाई ने माहौल और बिगाड़ दिया। उनके अनुसार, यह कार्रवाई कई लोगों की मृत्यु का कारण बनी जिसके लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार भाजपा सरकार है।

केजरीवाल-आतिशी के खिलाफ स्वाति ने फोड़ा ट्वीट बम

नईदिल्ली। आप सांसद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी पर निशाना साधा और उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और झूठ बोलते हैं कि आपने पूरी दिल्ली को साफ कर दिया है। ये तल्ख टिप्पणी उनके दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे के बाद आई है। मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया कि बुराड़ी में सड़कों की हालत खराब है, गलियों में बदबूदार पानी भरा हुआ है और जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बुराड़ी की हालत नरक से भी बदतर है। आतिशि ने एक्स पर लिखा कि कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे है कि मुझपे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है इसलिए भाजपा के इशारे पर मैंने ये सब किया। उन्होंने कहा कि ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने दो बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया।

हंगामेदार रहा पहला दिन, नहीं हो सका कामकाज, मोदी ने विपक्ष को धोया

नईदिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र का आज से आगाज हुआ है। हालांकि आगाज शोर शराबे वाला रहा। आज दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया जिसके बाद दोनों सदनों को स्थगित करना पड़ा है। 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक संसद का शीतकालीन सत्र चलेगा। यह सत्र काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। बताया जा रहा है कि सत्र में विचार के लिए वक्फ संशोधन विधेयक सहित 16 विधेयकों की सूची तैयार की गई है। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण विधेयकों को इस सत्र के दौरान पारित करने की कोशिश की जाएगी। मंगलवार को दोनों सदनों में कार्यवाही नहीं हो सकेगी क्योंकि संविधान दिवस है और इसपर स्पेशल आयोजन किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में 'महायुति' की प्रचंड जीत से उत्साहित सत्तापक्ष के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहुंचने पर 'मोदी-मोदी' के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तब केंद्रीय मंत्रियों समेत सत्तापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए। सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने 'जय भवानी' का नारा भी लगाया।

नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन्हें लोगों ने 80-90 बार खारिज कर दिया है, वे अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 'हुड़दंगबाजी' का सहारा लेकर संसद को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से सत्र के दौरान स्वस्थ चर्चा में भाग लेने का आह्वान भी किया और इसके परिणामकारी होने की उम्मीद भी जताई। मोदी ने कहा कि ऐसे मुट्ठीभर लोग अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सके और देश के लोगों ने उनके कार्यों को देखा और उचित समय पर उन्हें दंडित भी किया।

अदाणी समूह के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों के रिश्वतखोरी के आरोपों के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के चलते सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा की बैठक आरंभ होने पर सदन ने दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि नियम 267 के तहत उन्हें कुल 13 नोटिस मिले हैं।

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सोमवार को लोकसभा की बैठक एक बार के स्थगन के बाद पुनः शुरू होने के एक मिनट के अंदर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गयी और प्रश्नकाल समेत कोई विधायी कामकाज नहीं हुआ। निचले सदन की बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्तमान लोकसभा के सदस्य रहे वसंत राव चव्हाण और नूरुल इस्लाम तथा पूर्व सदस्यों एम एम लॉरेंस, एम पार्वती एवं हरीश चंद्र देवराव चव्हाण के निधन के बारे में सदन को सूचित किया। सभा ने कुछ क्षण मौन रखकर दिवंगत सांसदों और पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद कुछ विपक्षी सदस्य एक उद्योगपति से जुड़े मामले और उत्तर प्रदेश के संभल में रविवार को हुई हिंसा के मुद्दे को उठाने का प्रयास करते सुने गए और हंगामे के बीच बिरला ने करीब 11 बजकर पांच मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

संसद शुरू होते ही मोदी ने राहुल को दिया तगड़ा चैलेंज

चार सप्ताह के संसद शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने एक उत्पादक सत्र के लिए अपनी आशा व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि संसद के अंदर का मूड सर्दियों के मौसम की शांत और संयमित गुणवत्ता को प्रतिबिंबित करना चाहिए। भारत के मतदाता लोकतंत्र के प्रति समर्पित हैं, उनका समर्पण संविधान के प्रति है, उनकी आस्था संसदीय कार्य प्रणाली के प्रति है, संसद में बैठे हम सभी लोगों को जनभावनाओं पर खरा उतरना होगा और यही समय की मांग है इसकी भरपाई का एकमात्र तरीका यह है कि हमें सदन में हर विषय के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया और दावा किया कि चुनावों में जनता द्वारा बार-बार खारिज किए जाने के बावजूद कुछ लोग संसद पर नियंत्रण हासिल करने के लिए गुंडागर्दी का इस्तेमाल करते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वह बार-बार विपक्ष के साथियों से आग्रह करते रहे हैं और कुछ विपक्षी साथी भी चाहते हैं कि सदन में सुचारू रूप से काम हो। उन्होंने कहा कि लेकिन जिनको जनता ने लगातार नकारा है, वे अपने साथियों की बात को भी नकार देते हैं और उनकी एवं लोकतंत्र की भावनाओं का अनादर करते हैं। मोदी ने कहा कि आज विश्व भारत की तरफ बहुत आशा भरी नजर से देख रहा है, इसलिए संसद के समय का उपयोग वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़े हुए सम्मान को बल प्रदान करने में भी किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि संसद का यह सत्र अनेक प्रकार से विशेष है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे संविधान की यात्रा का 75वें साल में प्रवेश अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है। संसद का यह शीतकालीन सत्र 26 दिनों तक प्रस्तावित है और इस दौरान 19 बैठकें होंगी। हालांकि, संविधान दिवस समारोह के मद्देनजर 26 नवंबर को संसद की बैठक नहीं होगी। संविधान दिवस पर मुख्य कार्यक्रम संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया गया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। संसद के इसी केंद्रीय कक्ष में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया गया था।

लोकसभा में प्रधानमंत्री के पहुंचते ही लगे 'मोदी-मोदी' के नारे

महाराष्ट्र में 'महायुति' की प्रचंड जीत से उत्साहित सत्तापक्ष के सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पहुंचने पर 'मोदी-मोदी' के नारे लगाकर उनका अभिवादन किया। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी जब पहुंचे तक केंद्रीय मंत्रियों समेत सत्तापक्ष के सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और उन्होंने 'मोदी-मोदी' के नारे लगाए। सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने 'जय भवानी' का नारा भी लगाया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के हाल में घोषित नतीजों में सत्तारूढ़ 'महायुति' प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में कायम रहने में सफल रहा है। इस गठबंधन के घटक दलों में शामिल भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 132 सीट, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 57 और उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को 41 सीट हासिल हुईं। विपक्षी महा विकास आघाडी (एमवीए) के तीनों घटक दल राकांपा (शरदचंद्र पवार), कांग्रेस और शिवसेना (उबाठा) सामूहिक रूप से राज्य की 288 विधानसभा सीट में से केवल 46 पर ही जीत हासिल कर सके।

विपक्ष ने वक्फ विधेयक के लिए जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की

वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) में शामिल विपक्षी सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। इस दौरान विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की। इतना ही नहीं इन सदस्यों ने समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल को लेकर स्पीकर से शिकायत की और उन पर इस अहम मुद्दे पर कार्यवाही को जल्दबाजी में बढ़ाने का आरोप लगाया। लोकसभा अध्यक्ष को सौंपे ज्ञापन में विपक्ष ने समिति का कार्यकाल बढ़ाने की अपील की, ताकि इस विधेयक पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जा सके। डीएमके सांसद ए. राजा ने स्पीकर से मुलाकात के बाद कहा कि हमने उन्हें साफ बताया कि समिति के अध्यक्ष सही प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहे और वह जल्दबाजी में कार्यवाही को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। समिति के जिन सदस्यों ने स्पीकर से मुलाकात की, उनमें डीएमके नेता ए. राजा और एम अब्दुल्ला के अलावा कांग्रेस के सैयद नासिर हुसैन, मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद शामिल रहे। इसके अलावा तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और एम नदीमुल हक, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह, सपा से मोहिबुल्ला और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी शामिल रहे।

शीतकालीन सत्र की शुरुआत के साथ अडानी के मुद्दे पर विपक्ष का जोर! इंडिया गठबंधन की जेपीसी जांच की मांग

नईदिल्ली। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस जारी कर अडानी समूह के कथित कदाचार की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) बनाने पर चर्चा का आग्रह किया। नियम 267 राज्यों की परिषद में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों का हिस्सा है जो सदस्यों को तत्काल मामलों पर चर्चा करने के लिए नियमों के निलंबन के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को खड़गे के पत्र में कहा गया है, मैं राज्यों की परिषद (राज्यसभा) में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के नियम 267 के तहत नोटिस देता हूं।

25 नवंबर 2024 के लिए सूचीबद्ध व्यवसाय के निलंबन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का मेरा इरादा है। यह सदन एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के गठन पर चर्चा करने के लिए शून्यकाल और प्रश्नकाल और दिन के अन्य व्यवसायों से संबंधित प्रासंगिक नियमों को निलंबित करता है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अदानी समूह के भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप, विशेष रूप से भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) निविदा के संदर्भ में कथित कदाचार की जांच करना शामिल हैं।

खड़गे के पत्र में यह भी कहा गया है कि अडानी समूह द्वारा व्यापक स्टॉक हेरफेर, लेखांकन धोखाधड़ी, टैक्स हेवन के शोषण और ऋण के महत्वपूर्ण संचय के आरोपों पर भी चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक चालों का अडानी के अंतरराष्ट्रीय व्यापार विस्तार के साथ तालमेल पर गंभीर चिंताएं, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा की कीमत पर निजी हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्य मशीनरी के संभावित दुरुपयोग के बारे में सवाल उठा रही हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

पर्थ टेस्ट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दी 295 रनों से मात

पर्थ। टीम इंडिया ने पर्थ टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हराकर 5 मैचों की सीरीज में शानदार शुरुआत की। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भारत को जिस तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने घर पर हार का मुंह देखना पड़ा उसके बाद इस तरह का कमबैक भारत के लिए बेमिसाल है।

बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के शुरू होने से पहले ही टीम इंडिया को कई बुरी खबरें मिली थीं। जहां टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस मैच के लिए उपलब्ध नहीं थे। वहीं युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को भी वॉर्म अप मैच के दौरान चोट लग गई थी। अनुभवी तेज गेंदबाज शमी भी चोट के कारण दौरे के लिए नहीं चुने गए थे। तो प्लेइंग इलेवन में रविंद्र जडेजा और अश्विन जैसे अनुभवी स्पिनर भी नहीं थे। इसके बावजूद भारत ने पर्थ में ऐतिहासिक जीता हासिल की।

वहीं टीम इंडिया के जीत में सबसे अहम भूमिका कप्तान जसप्रीत बुमराह ने निभाई। बुमराह ने 8 विकेट लेकर गेंदबाजी से तो कमाल किया ही साथ ही कप्तानी से भी जीत में अहम रोलि निभाया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का उनका ही फैसला था जो कि सही साबित हुआ। उन्होंने सही समय पर गेंदबाजों को रोटेट किया और सही समय पर दूसरा पारी घोषित की। साथ ही इस मैच में टीम इंडिया की तरफ से युवा खिलाड़ियों ने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। यशस्वी जायवाल ने दूसरी पारी में शानदार प्रदर्शन करते हुए केएल राहुल के साथ टीम को मजबूत करने के लिए बेजोड़ पार्टनरशिप की। तो हर्षित राणा और नितीश रेड्डी को भी इस मैच के लिए डेब्यू का मौका मिला। जिन्होंने खुद को शानदार प्रदर्शन के बलबूते साबित किया। हर्षित राणा और नीतीश रेड्डी दोनों ही पहले टेस्ट में बेहद प्रभावी रहे। जहां हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड जैसे बेहतरीन बल्लेबाज को पवेलियन भेज कर टीम इंडिया को मजबूती दिलाई।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

शेयर बाजार में तूफानी तेजी से निवेशक मालामाल!

नईदिल्ली। भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में जोरदार रैली देखी गई। हाल की दिनों में गिरावट के बाद शेयर बाजार ने शानदार बाउंस बैक किया है। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स आज तूफानी तेजी के साथ 80,193.47 अंक पर खुला। कारोबार के दौरान यह 1300 से ज्यादा अंक चढ़कर 80,473.08 के स्तर तक पहुंच गया था। अंत में सेंसेक्स 1.25% या 992.74 अंक के उछाल के साथ 80,109.85 के लेवल पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी 1.32 प्रतिशत या 314.65 अंक चढ़कर 24,221.90 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी की 50 कंपनियों में से 43 के शेयर हरे निशान में बंद हुए। सेंसेक्स की कंपनियों में एलएंडटी का शेयर 4 प्रतिशत से ज्यादा चढ़कर बंद हुआ। साथ ही भारतीय स्टेट बैंक, अदानी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड आदि के शेयर भी लाभ में रहे।

सीएनजी की कीमत में दो रुपये की बढ़ोतरी

नयी दिल्ली। मुंबई के साथ-साथ देश के कई अन्य शहरों में सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, लेकिन चुनावी राज्य दिल्ली में उपभोक्ताओं को फिलहाल इससे छूट दी गई। राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी और खाना पकाने के लिए घरों में पाइप के जरिये प्राकृतिक गैस पहुंचाने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सप्ताहांत में सीएनजी की कीमत में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और अन्य शहरों में सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी की गई, लेकिन दिल्ली को इससे छूट दी गई है। एमजीएल की वेबसाइट के अनुसार, चुनाव समाप्त होने के साथ ही मुंबई में गैस की खुदरा बिक्री करने वाली महानगर गैस लिमिटेड (एमजीएल) ने मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में सीएनजी की कीमतों में दो रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी कर दी है।

एसएंडपी ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाया

नईदिल्ली। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगले दो वित्त वर्षों के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा दिया है। इसकी वजह ऊंची ब्याज दर से शहरी मांग में कमी आना है। अमेरिकी चुनाव परिणामों के बाद एशिया-प्रशांत अर्थव्यवस्थाओं के लिए अपने आर्थिक पूर्वानुमान को अपडेट करने हुए रेटिंग एजेंसी ने वित्त 2025-26 (अप्रैल 2025 से मार्च 2026) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) ग्रोथ 6.7 फीसदी और वित्त 2026-27 में 6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। यह पिछले अनुमानों क्रमशः 6.9 फीसदी और 5 फीसदी से कम है। एसएंडपी ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.8 फीसदी रहने का अनुमान लगाया हे। रेटिंग एजेंसी को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027-28 में जीडीपी ग्रोथ रेट 5 फीसदी रहेगी। एसएंडपी ने चीन के लिए 2024 में 4.8 फीसदी की ग्रोथ का अनुमान बरकरार रखा।

सोने में 5 दिनों की तेजी पर ब्रेक, 1,500 रुपये हुआ सस्ता

नईदिल्ली। लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद आज सोमवार 25 नवंबर को सोने की कीमतों में जबरदस्त नरमी देखी जा रही है। घरेलू बाजार में आज सोना 1,369 रुपये कमजोर हुआ है। एमसीएक्स पर आज भाव 76,316 (बिना जीएसटी शामिल किए) रुपये प्रति 10 ग्राम तक नीचे चला गया जबकि पिछले हफ्ते 77,685 रुपये प्रति 10 ग्राम की ऊंचाई तक पहुंचा था। पिछले हफ्ते घरेलू बाजार में सोना तकरीबन 4,500 रुपये मजबूत हुआ था। ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में लगातार 5 दिनों की तेजी के बाद दिख रही नरमी के मद्देनजर घरेलू बाजार में सोना कमजोर हुआ है। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी के बावजूद ग्लोबल मार्केट में निवेशक फिलहाल ऊपरी स्तरों पर मुनाफावसूली कर रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में आई मजबूती ने भी घरेलू बाजार में एक हद तक सोने पर दबाव बनाया है।

पूरे विश्व के लिए आदर्श है 'सहकार से समृद्धि' का भारतीय दर्शन

अमित शाह

सहकारिता एक ऐसी व्यवस्था है, जो समाज में आर्थिक रूप से आकांक्षी लोगों को न सिर्फ समृद्ध बनाती है, बल्कि उन्हें अर्थव्यवस्था की व्यापक मुख्यधारा का हिस्सा भी बनाती है। सहकारिता बिना पूंजी या कम पूंजी वाले लोगों को समृद्ध बनाने का एक बहुत बड़ा साधन है। सहकारिता के माध्यम से भारत इन लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में सहकारिता की एक विस्तृत परंपरा तो रही है, लेकिन आजादी से पहले सहकारिता जिस प्रकार आर्थिक आंदोलन का माध्यम बनी, उसे और भी अधिक ऊर्जा और शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में शुरू हुआ। वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने सहकारिता का स्वायत्त मंत्रालय स्थापित कर सहकारिता के लिए अवसरों के सारे बंद दरवाजे खोल दिए। महज 3 वर्षों में देश में सहकारिता को मजबूत बनाने के लिए जितने कदम उठाए गए हैं, उससे भारत अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ सहकारी क्षेत्र में भी 'विश्वमित्र' बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अब भारत का सहकारिता आंदोलन एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने जा रहा है। देश 25-30 नवंबर, 2024 को दिल्ली में 'अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आई.सी.ए.) महासभा' और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी करने को तैयार है। आई.सी.ए. के 130 वर्ष के इतिहास में यह पहला मौका है, जब भारत इसका आयोजक होगा। इस सम्मेलन से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का भी शुभारंभ होगा। आई.सी.ए. महासभा और वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी वैश्विक सहकारी आंदोलन में भारत के नेतृत्व की

स्वीकार्यता का प्रतीक है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद से निरंतर समाज के पिछड़े, अति पिछड़े, गरीब और विकास की दौड़ में पीछे छूट चुके लोगों के उत्थान की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मोदी सरकार मानती है कि यह परिवर्तन सहकारिता आंदोलन को मजबूत किए बिना नहीं हो सकता। यह आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब भारत ने सहकारी आंदोलन के पुनरुत्थान की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। कमजोर पड़ रही सहकारी संस्थाओं के सशक्तिकरण से लेकर उनके व्यापार को सरल बनाना, समितियों में पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए मजबूत प्रशासनिक, नीतिगत और कानूनी उपाय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'सहकार से समृद्धि' का मंत्र दिया है, जिसका उद्देश्य देश की सहकारी संस्थाओं को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाना है। देश में सहकारी तंत्र का विस्तार कर एक नया आर्थिक मॉडल खड़ा किया जा रहा है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने में सहायक साबित होगा। दुनिया के अन्य देशों के लिए यह एक विकास मॉडल के रूप में सामने आएगा। भारत में प्राचीन काल से ही सहकारिता का एक समृद्ध इतिहास रहा है। इसके संकेत कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। दक्षिण भारत में भी 'निधियों' का प्रचलन सहकारी वित्तीय व्यवस्था की झलक प्रदान करता है। पाश्चात्य विचारों से प्रभावित कई अर्थशास्त्रियों ने 21वीं सदी की शुरूआत में ही यह चर्चा प्रारंभ कर दी थी कि सहकारिता का विचार आधुनिक युग में कालबाह्य हो गया है। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में किसी 3 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ जनसंख्या वाले देशों का आर्थिक मॉडल उपयुक्त नहीं हो सकता। देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, आर्थिक विकास के सभी मानकों में वृद्धि के साथ-साथ यह आवश्यक है कि 140 करोड़ लोगों की समृद्धि हो, सभी व्यक्तियों को काम मिले और उन्हें सम्मान से जीने का अधिकार भी प्राप्त हो, और यह केवल सहकारिता के माध्यम से ही संभव है। देश के इतिहास में इसके कई उदाहरण भी हैं। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-आप्रेटिव बैंक ने पिछले 100 वर्ष में 100 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। बैंक न केवल अपने एन.पी.ए. को शून्य पर बनाए रखने में सफल रहा है बल्कि उसके पास 6,500 करोड़ रुपए से अधिक की जमाराशि भी है।

डबल इंजन की सरकार में तेज रफ्तार से चल रही है छत्तीसगढ़ में विकास की रेलः साय

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ में अब तेज रफ्तार से विकास की रेल चल रही है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कल रायपुर से बिलासपुर तक की अपनी ट्रेन यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के तेजी से विकास के संकल्प को पुनः दोहराया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि पिछले 10 सालों में रेलवे के क्षेत्र में जो सकारात्मक बदलाव हुए, इसने न केवल यात्री सुविधाएं बढ़ी हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है।

उन्होंने कहा रेलवे के आधुनिकीकरण से रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। रेलवे नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को बड़े शहरों से जोड़ा जा रहा है, जिससे व्यापार और पर्यटन को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं न केवल यात्री कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी, बल्कि औद्योगिक और खनिज संसाधनों के परिवहन को भी सुगम बनाएंगी। इनके अलावा, राज्य में कई अन्य छोटी रेल लाइन और मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएं भी योजना में हैं, जो क्षेत्रीय विकास और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में जहां-जहां रेल परिवहन की आवश्यकता महसूस की जाएगी, उस दिशा में तेजी से पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस यात्रा से मुझे बहुत कुछ जानने समझने का सुंदर अवसर मिला था।

हम यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने और उनके समस्याओं के समाधान की दिशा में केंद्र सरकार के सहयोग से आवश्यक कदम उठाएंगे

स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैंः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे भारत, तेजस और गतिमान जैसी हाई-स्पीड ट्रेनों ने यात्रा समय को काफी घटा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रेलवे के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आधुनिक ट्रेनों में वातानुकूलित डिब्बे, आरामदायक सीटें, वाई-फाई, ऑनबोर्ड कैटरिंग सुविधा मिल रही है। स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिसने यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाया है। उन्होंने कहा कि ई-टिकटिंग और डिजिटल भुगतान ने बुकिंग प्रक्रिया को सरल और तेज बना दिया है। सौर ऊर्जा और बायो-टॉयलेट जैसी पहल पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद कर रही हैं। भारतीय रेलवे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिटिक्स और ऑटोमेशन जैसे आधुनिक तकनीकी उपायों के उपयोग की ओर आगे बढ़ रहा है, ताकि दक्षता और सेवा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा है कि प्रदेश की आर्थिक तरक्की के लिए रेल परिवहन के समुचित उपयोग की ओर तेजी से आगे बढ़ा जाए। इसी क्रम में केंद्र सरकार के सहयोग से कई रेल परियोजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है और कई ऐसी परियोजनाएं हैं, जिनको विस्तार दिए जाने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा है कि डोंगरगढ़-कवर्धा-कटघोरा रेल लाइन परियोजना के लिए रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल चुकी है। यह परियोजना लगभग 295 किलोमीटर लंबी होगी और इसकी अनुमानित लागत 4021 करोड़ रुपये है। इस रेल लाइन का निर्माण छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस रेल लाइन में डोंगरगढ़ से कवर्धा के बीच 12 और कवर्धा से कटघोरा के बीच 15 स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र में यात्री सुविधा बढ़ाएगी बल्कि खनिजों के परिवहन और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत सरकार और रेल मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में कई नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनका उद्देश्य राज्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और कनेक्टिविटी बढ़ाना है। कोरबा-अंबिकापुर नई रेल लाइन 180 किलोमीटर लंबी परियोजना है, जिसके सर्वेक्षण और डीपीआर के लिए 16.75 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना सरगुजा क्षेत्र में विकास को गति देगी। उसी प्रकार गढ़चिरौली-बीजापुर-बचेली तक 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन के सर्वेक्षण के लिए 12.25 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। यह परियोजना सुदूर क्षेत्रों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों से जोड़ने में मदद करेगी। सरडेगा-भालुमुडा डबल लाइन 37 किलोमीटर लंबी परियोजना ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। इस परियोजना के लिए 1360 करोड़ रुपये का प्रावधान है।छत्तीसगढ़ में अम्बिकापुर-बरवाडीह, खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा, रावघाट-जगदलपुर और धरमजयगढ़-पत्थलगांव-लोहरदगा रेल परियोजनाओं का डीपीआर तैयार हो रहा है। धरमजयगढ़-लोहरदगा परियोजना के लिए रेलवे द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण का काम अंतिम चरण में है।

संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश में होंगे वर्ष भर कार्यक्रम

रायपुर। संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए राज्य के स्कूल, कॉलेज और ग्राम पंचायतों में साल भर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा।

इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए 'हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान' का टैगलाइन निर्धारित किया गया है। संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। अनुसूचित जाति, जनजाति गांवों में

15 दिवसीय संविधान यात्रा निकाली जाएगी।

यात्रा के दौरान, जहां भी बाबा साहेब की प्रतिमाएं होंगी, उन पर पुष्पांजलि अर्पित किया जाएगा। ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाओं का भी आयोजन होगा, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 51ए के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को पढ़ा और समझाया जाएगा। इस मौके पर जीवित स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों से जुड़े गांवों में, जिसमें संविधान सभा की महिला सदस्यों के योगदान पर विशेष जोर देते हुए विशेष समारोह आयोजित किए जाएंगे।

स्कूलों और कॉलेजों में प्रश्नोत्तरी वाद-विवाद एवं भाषण प्रतियोगिता

स्कूलों और कॉलेजों में संविधान के प्रावधान, संविधान निर्माण की प्रक्रिया, मौलिक अधिकार, कर्तव्य एवं राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांत तथा नवीनतम संशोधन आदि विषयों पर प्रश्नोत्तरी आयोजित किया जाएगा। साथ ही नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों तथा अन्य संवैधानिक मुद्दों पर वाद-विवाद सेमिनार, जिसमें सामाजिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, समय के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए संविधान को लचीला बनाने तथा नवीनतम तथा प्रमुख संशोधनों की जानकारी देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

जीवन में स्पार्क रहे तो फिर क्यों कुछ डार्क रहेः गिरीश पंकज

रेडियो स्पार्क के शुभारंभ पर वरिष्ठ पत्रकार व साहित्यकार गिरीश पंकज ने सुनाई कविता

रायपुर। जीवन में स्पार्क रहे, तो फिर क्यों कुछ डार्क रहे, ऐसा कुछ काम करें हम जग में, सदियों उसकी मार्क रहे। इन्हीं पंक्तियों के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं साहित्यकार गिरीश पंकज ने अपनी कविता पढ़ी। वे रायपुर के वृंदावन हाल में रेडियो स्पार्क के शुभारंभ के अवसर पर संबोधित कर रहे थे। रेडियो स्पार्क की डायरेक्टर वर्षा भिवगड़े ने बताया कि यह रेडियो छत्तीसगढ़ी भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए खोला गया है। संयोजक शांता शर्मा ने बताया कि यह छत्तीसगढ़ी कलाकारों के लिए एक अच्छा मंच है जहाँ वे अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। यह डोंगरगढ़ का पहला रेडियो है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवि मीर अली मीर भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता नन्दा जाही का रे का पाठ किया। वरिष्ठ पत्रकार अंशुमन शर्मा ने कहा कि ऐसा कुछ कम करो कि लोग आपसे नौकरी मांगे। उन्होंने अपनी प्रतिभा, नवाचार पर जोर दिया और युवाओं को संदेश दिया। प्रोफेसर डॉ शाहिद अली ने कहा कि काम ऐसा करो कि लोग आपको सिर्फ नाम से नहीं आपके काम और प्रतिभा से याद रखें। कवियत्री अन्नपूर्णा पवार ने नारी शक्ति पर कविता सुनाई। कार्यक्रम में मोर रायपुर फेम् अभिनंदन ग्रुप के दिव्यांग बच्चों ने शानदार प्रस्तुति दी। वरिष्ठ पत्रकार डॉ अवधेश मिश्रा, कैलाश जायसवाल, कमल शर्मा, आरएसएस से शिरीष अग्रवाल, समाजसेवी पवन अग्रवाल, डॉ टोपेश शुक्ला ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में पंडवानी गायिका हेमलता पटेल, छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर बनाने वाले ईश्वर साहू, धनेश साहू, संगीता शर्मा आदि लोग उपस्थित थे।

अपराधी राह चलते चाकू मार रहे, गोलियां चल रही, हत्याएं हो रही, पुलिस आंकड़ों का खेल खेल रही

रायपुर। पुलिस के द्वारा राजधानी में अपराध के आंकड़े कम होने का दावा खारिज करते हुये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि राजधानी में कानून व्यवस्था की स्थिति बेलगाम हो चुकी है।

अपराधों पर अंकुश लगाने के बजाय पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। नागरिक रोज चाकुओं से गोदे जा रहे, गोलियां चल रही, बस स्टैण्ड में महिला के साथ बलात्कार हो रहा, सिपाही की प्रताड़ना से आम आदमी आत्महत्या कर रहा, सूखे नशा करके अपराधी राह चलते चाकू मार रहे, पुलिस आंकड़ों का खेल खेल रही है। पुलिस के आंकड़े डरे सहमे शहरी के जले पर नमक छिड़कने वाले है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में अपराधी बेलगाम हो गये है। आम आदमी अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहा है। रायपुर शहर में नवंबर माह में 23 से अधिक हत्याएं हुई है। प्रदेश का हर नागरिक डरा हुआ है। महिलायें असुरक्षित है। बलात्कार, सामूहिक बलात्कार

की घटनाएं बढ़ गयी है। एक ही दिन में राजधानी के विधानसभा के पास आमासिवनी में शराब दुकान के सामने दो-दो हत्याये हुई, पुरानी बस्ती थाने के चंद कदमों की दूरी पर पेट्रोल डालकर एक युवक को जिंदा जला दिया गया, तेलीबांधा में गवाह को धमकाने अपराधियों ने हमला कर दिया, दिनदहाड़े गोलियां चल रही है, गैंगवार हो रहे हैं।

दीवाली के दिन ही राजधानी रायपुर में 9 हत्या हुई, दुर्ग में 4 हत्यायें हुई। रायपुर में रोज हत्याएं हो रही है लेकिन यह सरकार आपराधिक घटनाओं को रोकने में पूरी तरह नाकाम रही है। राजधानी में 11 माह में 5 गोली कांड हुआ, अंतरराज्यीय गैंगस्टर रायपुर तक पहुंच गये।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सबसे संवेदनशील और सुरक्षित माने जाने वाले रायपुर के सेन्ट्रल जेल परिसर के सामने एक व्यक्ति को गोली मार दी गयी। गृहमंत्री के जिले से बेलगाम हुआ अपराध मुख्यमंत्री के गृह ग्राम तक पहुंच गया। राजधानी रायपुर में चला हत्याओं का गोलीबारी का खौफनाक मंजर पूरे प्रदेश में फैल चुका है।

आम आदमी अपने आपको भयभीत महसूस कर रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर अपराध का गढ़ बन गया है। सरकार की लापरवाही और पुलिस की नाकामी का परिणाम है कि छत्तीसगढ़ में कोई भी सुरक्षित नहीं है।

प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है राजधानी में सरेआम गोलीबारी की पांचवी घटना हुई है।

सरकार की नाकामी और पुलिस की लापरवाही का परिणाम है कि प्रदेश की राजधानी असुरक्षित हो चुकी है।

मुख्यमंत्री के सलाहकार मोदी सरकार को ही अडानी का उपक्रम समझते है - कांग्रेस

रायपुर। मुख्यमंत्री के सलाहकार पंकज झा अडानी को ही भारत सरकार समझ रहे तो इसमें कोई क्या कर सकता है। भूपेश सरकार ने 2021 में भारत सरकार के उपक्रम सेकी से अनुबंध किया था। पंकज झा उसको अडानी से अनुबंध बता रहे, मतलब भाजपा की निगाह में मोदी सरकार ही अडानी है। झा बताये जो दस्तावेज उन्होंने खुद जारी किया था उस अनुबंध में अडानी के साथ कहां अनुबंध हुआ है। सेकी ने राज्य सरकार से अनुबंध करने के बाद अडानी, अंबानी, माल्या, चौकसे, अर्णवमोदी किससे अनुबंध किया इसको तो मोदी सरकार और भाजपा ही बता सकती है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 अगस्त 2021 में सेकी याने सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (भारतीय सौर ऊर्जा निगम) के साथ समझौता किया था। जिसमें सेकी की तरफ से उसके वरिष्ठ प्रबंधक शिवाशीष दास एवं बतौर गवाह सेबी के उप प्रबंधक तरूण मुखीजा ने हस्ताक्षर किया था तथा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सीएसपीडीसीएल (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी) के इज्यूक्यूटिव डायरेक्टर एचपी मंगीपुडी एवं एडीशन चीफ इंजीनियर तथा अजय कुमार सिंह सुपरिटेंडेट इंजीनियर ने हस्ताक्षर किया था इस अनुबंध में अडानी न पार्टी था और न ही अडानी समूह के किसी प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था।

सरकार की लापरवाही के चलते मंत्री भी सड़क हादसा का शिकार हो रहेः धनंजय

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के काफिले में गाय घुसने से हुई दुर्घटना के बाद भी परिवहन विभाग, पुलिस प्रशासन, पीडब्लूडी, पशुपालन विभाग नही चेता था। जिसका ही नतीजा है सरकार के दो मंत्री और सड़क हादसा का शिकार हो गये। जब वीआईपी सुरक्षा, फॉलो गार्ड, रोड़ क्लीयरेंस पार्टी के साथ चलने वाले लोग दुर्घटना ग्रस्त हो जा रहे है। ऐसे में समझ सकते है आम जनता अपने परिजनों के साथ कितने जोखिम उठाकर स्टेट एवं नेशनल हाइवे पर यात्रा करते है। ये सब खराब सड़क, बेतरतीब यातायात व्यवस्था, नशाखोरी, जिम्मेदार विभागो की लापरवाही के चलते ही हो रहा है। रोज हो रहे सड़क दुर्घटना के बावूजद सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार की उदासीनता नजर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार सड़कों की दशा सुधारने में रुचि नहीं दिख रही है। परिवहन विभाग वसूली में मस्त है और यातायात विभाग तो बस खानापूर्ति कर रही है। स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे में जिस प्रकार से तेज गति से भारी वाहन चल रहे हैं, बसें चल रही है, मोटरसाइकिल चल रही है, सड़क के आजू-बाजू जो बड़ी-बड़ी वाहने खड़े हो जा रही है यह सब दुर्घटना का मुख्य कारण है। सरकार को इन विषयों पर ध्यान देना चाहिए और प्रदेश की जनता की जान माल की सुरक्षा करनी चाहिए।

ग्राम छरछेद में टोनही प्रताड़ना से पीड़ित परिवार से मिले डा. दिनेश

रायपुर। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष डॉ दिनेश मिश्र ने बताया समिति के सदस्यों ने कसडोल के ग्राम छरछेद का दौरा कर जादू टोना के संदेह में प्रताड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की,उन्हें सांत्वना दी तथा उन्हें ढाढस बंधाया। समिति के सदस्यों की टीम में डॉ.दिनेश मिश्र ,डॉ. शैलेश जाधव, डॉ. एच. के एस गजेंद्र शामिल रहे। समिति के सदस्य कसडोल के छरछेद जाकर केवट परिवार से मिले, जहां पिछले सितंबर में चार सदस्यों की हत्या जादू टोने के संदेह में कर दी गई थी, जिसमें से एक मृतक 11 माह का मासूम बच्चा भी था। उक्त परिवार की सदस्य वरिष्ठ सदस्य मोगरा बाई केवट जिस पर जादू टोना करके बीमार करने का शक किया जा रहा था,

समिति ने उससे व उसकी बेटी चार बाई से बातचीत की। मोगरा बाई बताया कि वह तो खुद के इलाज के लिए गांव से बाहर गई थी इस बीच पड़ोस के छह लोगों ने आकर उनके परिवार के सदस्यों पर घातक हमला किया जो घर के एक कमरे में बैठे हुए थे। हमलावर द्वारा पत्थर तोडने के घन और घातक हथियारों से किए गए वार से सभी सदस्यों चेतराम , जमुना बाई केवट, यशोदा बाई केवट और एक साल के बच्चे की मृत्यु हो गई और जब वह अपना उपचार करने के बाद लौट कर आई .तब उसने देखा ,घर में मजमा लगा हुआ था। उन्होंने उसकी बेटी ने बताया उनके पूरे गांव में किसी भी व्यक्ति से कोई व्यक्ति गत परेशानी, रंजिश नहीं है और भी मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। इस प्रकार की घटना होने से न केवल अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बल्कि अन्य आर्थिक समस्या भी पैदा हो गई है। उन्हें अब तक शासन द्वारा घोषित मुआवजा भी प्राप्त नहीं हुआ है जिसकी सितंबर में घोषणा की गई थी. डॉ.दिनेश मिश्र ने वहां उपस्थित ग्रामीणों से कहा जादू टोने जैसी बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता है।

बारदाने की कमी, टोकन सिस्टम का गलत फर्मान से धान बेचने में परेशानी

रायपुर। धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था, बारदानों की कमी तथा टोकन के लिये सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशो तथा मीलरों द्वारा धान का उठाव नहीं करने के कारण किसान परेशान है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार धान खरीदी सुचारू रूप से चलाने का झूठा दावा कर रही है। सरकार किसानों को तथा समस्या उठाने वालों को धमकाने के बजाय कमियां दुरूस्त करें। धान खरीदी केन्द्रों में फैली अव्यवस्था और सरकार द्वारा जारी फरमान के कारण किसानों को धान बेचने में परेशानी हो रही। सरकार दावा कर रही है कि सभी किसानों का पूरा

धान 21 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जायेगा, लेकिन जिस रफ्तार से धान खरीदी हो रही है। सरकार द्वारा घोषित लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी होना असंभव है। सरकार के द्वारा 14 नवंबर से 31 जनवरी तक कुल 75 दिन के अंदर धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित है, इसमें से 30 दिनों लगभग एक महिना से अधिक छुट्टी है, अर्थात लगभग 45 दिन ही सरकार धान खरीदी करेगी। मात्र 45 दिनों में 30 लाख से अधिक किसानों के धान की खरीदी संभव नही। प्रतिदिन 3.5 लाख से 4 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की जायेगी तभी निर्धारित लक्ष्य 160 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो पायेगी। पंजीकृत किसानों की संख्या बढ़ी है। रकबा बढ़ा है, पैदावार बढ़ा है, पैदावार भी ज्यादा हुआ है। प्रति एकड़ खरीदी की लिमिट भी बढ़ी है, अतः धान खरीदी अवधि अभी से बढ़ाने की घोषणा की जाये। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि समितियों में बारदाने की कमी है। सरकार ने कहा है कि 50 प्रतिशत नये 50 प्रतिशत पुराने बारदानों का उपयोग किया जाये। 50 प्रतिशत पुराने बरदाने समितियों में पहुंचे ही नहीं है, जिसके कारण धान खरीदी बाधित हो रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि टोकन काटने के बाद भी किसान अपना धान बेच नहीं पा रहे है.

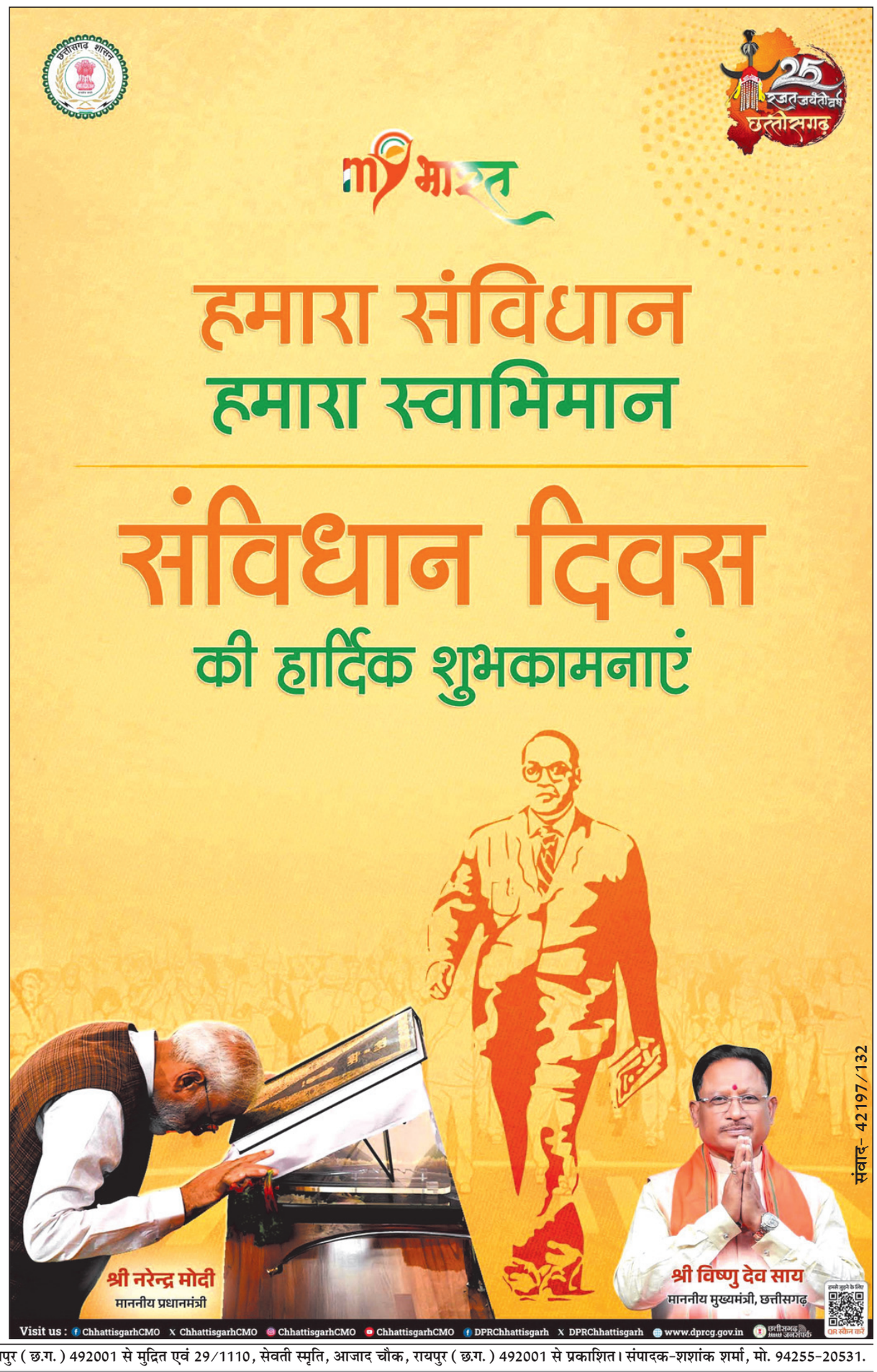

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.